राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 224 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शुक्रवार ,05 फरवरी 2021 , मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

गोवा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में फिर से जान फूंकने के लिए केन्द्र से मांगी मदद

पणजी, (वेबवार्ता)। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए पर्यटन क्षेत्र में फिर से जान फूंकने के लिए केन्द्र से आर्थिक सहायता मांगी है। सावंत ने पत्रकारों को बुधवार को बताया कि उन्होंने पर्यटन क्षेत्र की मदद करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। राज्य में सबसे अधिक राजस्व इसी क्षेत्र से आता है। मुख्यमंत्री ने कहा, '' वैश्विक महामारी के कारण पर्यटन जगत काफी प्रभावित हुआ है और उसमें फिर से जान फूंकने के लिए केन्द्र के मदद की दरकार है।'' केन्द्र से कितनी राशि की आर्थिक मदद मांगी गई है, इसके बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी नहीं दी। सावंत ने कहा, '' मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार हमारी मांग पर गौर करेगी।'' उन्होंने कहा कि खनन उद्योग के बंद होने से भी राज्य का राजस्व प्रभावित हुआ है।

झारखंड में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर दो हजार रुपये की सम्मान राशि मिलेगी

रांची, (वेबवार्ता)। झारखंड सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए आगे आने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 'नेक आदमी' नीति को स्वीकृति दी है। इसके तहत घायलों को दुर्घटना के प्रथम घंटे में अस्पताल पहुंचाने में मदद देने वाले व्यक्ति को 'नेक आदमी' का तमगा देते हुए दो हजार रुपये देकर सम्मानित किया जायेगा और इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को पुलिस पूछताछ के नाम पर तंग न करे। इस नीति के तहत अत्यावश्यक होने पर पूछताछ के लिए ऐसे लोगों को पुलिस अगर बुलायेगी तो प्रत्येक बार व्यक्ति के खाते में एक हजार रुपये पुलिस को जमा करने होंगे। राज्य सरकार की विज्ञप्ति में बुधवार को इस बात की जानकारी देते हुए बताया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया।

कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों को एमआरएनए के केवल एक खुराक की जरूरत हो सकती है: वैज्ञानिक

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हुए लोगों को टीके की दो खुराक के बजाए केवल एक खुराक की जरूरत हो सकती है अगर वे मॉडर्ना या फाइजर का कोविड-19 क टीका लगवा रहे हैं। यह जानकारी एक अध्ययन में दी गई है जिसमें टीके की आपूर्ति सीमित संख्या में होने की स्थिति में खुराक कम करने के तरीके सुझाए गए हैं। विशेषज्ञों ने इस अध्ययन की अभी समीक्षा नहीं की है और न ही यह अभी प्रकाशित हुआ है। इसमें 109 व्यक्तियों में रोग प्रतिरोधी क्षमता का आकलन किया गया है। अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक एमआरएनए टीका की एक खुराक उन व्यक्तियों में ज्यादा असरदार होता है जो वायरस से उबर चुके हैं और उनमें कोरोना वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी हुई है। अनुसंधानकर्ताओं में अमेरिका के इकान स्कूल ऑफ मेडिसिन के फ्लोरियन क्रैमर भी शामिल हैं। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने लिखा है, ''सार्स कोव-2 से जो लोग उबर चुके हैं उनमें टीके की पहली खुराक 'बूस्टर खुराक' का काम करती है।'' अध्ययन में वैज्ञानिकों ने एमआरएनए टीकों का विश्लेषण किया जिसमें वायरल जेनेटिक सामग्री के हिस्सों का इस्तेमाल किया गया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि कोविड-19 से उबर चुके रोगियों में टीका लगाए जाने के बाद रोग प्रतिरोधक के स्तर की तुलना उन लोगों से की गई जिन्हें संक्रमण नहीं हुआ और जिन्हें टीके की दो खुराक लगाई गई। एक अन्य शोध में स्वास्थ्यकर्मियों को दिए गए फाइजर-बायोएनटेक या मॉडर्ना टीके के एकल खुराक पर रोग प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन किया गया।

केजरीवाल ने की स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को काफी कम करना है और हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक दिल्ली में जितने वाहन खरीदे जाते हैं उसमें 25 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक हों।

चौरी-चौरा के संग्राम में भी किसानों की थी बहुत बड़ी भूमिका : नरेंद्र मोदी

गोरखपुर । देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने के साथ अंग्रेजों को चुनौती देने वाले गोरखपुर के चौरी चौरा कांड का आज शताब्दी वर्ष है। गोरखपुर में इसके शताब्दी महोत्सव का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी की खातिर अपना जीवन बलिदान करने वाले बलिदानियों को नमन किया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौरी-चौरा कांड पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि चौरी-चौरा के बलिदानी हो वीर शहीदों के चरणों में प्रणाम करता हूं आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। चौरीचौरा की पवित्र भूमि पर देश के लिए बलिदान होने वाले और देश के स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा देने वाले वीरों को प्रणाम करता हूं। देश जब आजादी के 77वे बरस में प्रवेश कर रहा है। यह आयोजन उसे और महत्वपूर्ण बना दे रहा है।

कोरोना काल में आई चुनौतियों के समाधान को नई तेजी देगा बजट = इस संग्राम के सेनानियों को हल ही इतिहास केपन्नों में जगह न दी गयी हो, लेकिन उनके प्रयास ने महत्वपूर्ण कार्य किया। सभी मां भारती की वीर संतान थे। ऐसी बहुत कम घटना होगी जिसमें एक साथ 19 लोगों को फांसी दी गयी। आजादी के आंदोलन में ऐसी बहुत कम घटना होगी जिसमें एक ही घटना में 19 संग्राम सेनानियों को फांसी पर लटका दिया गया हो। महामना के प्रयासों से डेढ़ सौ लोगों को फांसी से बचा लिया गया। आज का दिन बाबा राघव दास और महामना जी को भी प्रणाम करने का है। ब्रितानी हुकूमत 172 लोगों को फांसी देने पर उतारू थी लेकिन बाबा राघवदास व महामना मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 150 से अधिक की जान बवह ली। आज भारत खुद कोरोना की वैक्सीन बना रहा है। दुनिया के बड़े देशों से तेजी से टीकाकरण कर रहा है तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा को गर्व महसूस हो रहा होगा।

भारत ने कोरोना काल में 150 से अधिक देशों के नागरिकों को दवाई भेजी। मदद पहुंचाई। हजारों नागरिकों को सुरक्षित उनके देश भेजा। दुनिया के बड़े-बड़े देशों से भी तेज गति से टीकाकरण कर रहा है। कोरोना काल मे देश के सामने जो चुनौतियां आई उनके समाधान को यह बजट नई तेजी देने वाला है। पहले कई दिग्गज कह रहे थे कि इतने संकट के बाद कर लगाना पड़ेगा लेकिन देह वाशियों पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया। सरकार ने ज्यादा से जुड़ खर्च करने का फैसला किया। पीएम मोदी ने कहा कि गांव को बाजार व मंडी से जोड़ने, पूप बनाने, रेल की पटरी बिछाने, शिक्षा, रेल बस चलाने, स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जाएगा। इन कार्यो के लिए काम करने वालों की भी जरूरत होगी। निर्माण के लिए लोगों की जरूरत होगी। रोजगार मिलेगा। दशकों से बजट का मतलब सिर्फ घोषणा ही रह गई थी। बजट को हिसाब किताब का बही खाता बना दिया गया था। पहले की सरकारों ने बजट ऊ ऐसी घोषणाओं का माध्यम बन दिया था जिसे पूरा ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब सोच व अप्रोच बदल दिया गया है। हमारे टीकाकरण अभियान से दुनिया के कई देश सीख रहे हैं। गोरखपुर में ले और सिक्स लेन सड़क बन रही है गोरखपुर से 8 शहरों के लिए फ्लाइट की सुविधा भी है कुशीनगर में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टूरिज्म सेक्टर को आगे बढ़ाया गया। कुशीनगर का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर्यटन को बढ़ावा देगा विकास का यह कार्य शहीदों के लिए श्रद्धांजलि होगी। विश्वास है कि जो यात्रा हमने अहरु की है उसे एक नए भारत के निर्माण के साथ पूरा करेंगे। जो यात्रा हमने ने शुरू की है वह नए भारत के निर्माण के साथ पूरी करेंगे

पीएम ने कहा कि जो शहीद हुए उनके कारण हम स्वतंत्र हुए। एक बात न भूलें कि वे देश के लिए शहीद हुए इसलिये हम स्वतंत्र हुए। देश के लिए जीने का संकल्प लें। हमें सौभाग्य मिला है देश के लिए जीने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी-चौरा शताब्दी समारोह में चौरी-चौरा पर एक डाक टिकट जारी किया।

देशभर में 6 फरवरी को होगा चक्का जाम, राकेश टिकैत बोले- दिल्ली से दूर रहेंगे

" राकेश टिकैत ने सरकार पर बातचीत नहीं करने का आरोप लगाया। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पहले की तरह कमेटी से बात कर लें। लेकिन वे (सरकार) बात नहीं कर रहे क्योंकि वे इस आंदोलन को लंबा चलाना चाहते हैं। हम बातचीत के लिए कहते रहेंगे कि बात करो..

नयी दिल्ली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने विदेशियों से मिल रहे समर्थन पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोई विदेशी समर्थन कर रहा है तो क्या दिक्कत है ? हालांकि उन्होंने विदेशी हस्तियों को जानने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पॉप रॉकस्टार रिहाना, पॉर्न स्टार मिया खलीफा, पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग समेत कई हस्तियों ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था। जिस पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी।

किसान नेता राकेश टिकैत ने 6 फरवरी को पूरे देश में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करने की बात कही। हालांकि यह चक्का जाम राजधानी दिल्ली से दूर होगा। उन्होंने कहा कि चक्का जाम होने की वजह से जिन लोगों को परेशानी होगी उनके लिए पानी, लंगर, चना और मूंगफली का इंतेजाम किया जाएगा और इन लोगों को बताएंगे कि यह सब सरकार कर रही है। लेकिन जब संवाददाताओं ने राकेश टिकैत से पूछा कि यह सब इंतेजाम कैसे होंगे तो उन्होंने कहा कि यह सब गांव वाले कर लेंगे।

राकेश टिकैत ने सरकार पर बातचीत नहीं करने का आरोप लगाया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पहले की तरह कमेटी (संयुक्त किसान मोर्चा) से बात कर लें।

लेकिन वे (सरकार) बात नहीं कर रहे क्योंकि वे इस आंदोलन को लंबा चलाना चाहते हैं। हम बातचीत के लिए कहते रहेंगे कि बात करो।

रामपुर में बोलीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा, किसानों पर बड़ा जुल्म कर रही सरकार

मुरादाबाद । रामपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों पर बड़ा जुल्म कर रही है। उनका दुख-दर्द सुनने के बजाय उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उनके आंदोलन को साजिश समझ रही है और उन्हें आतंकवादी बता रही है, जब तक तीनों काले कानूनों को सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

बिलासपुर के डिबडिबा गांव में ट्रैक्टर परेड में मृतक नवरीत सिंह के भोज कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचीं प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हम शहीद नवरीत की याद में आए हैं। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि यह शहीद हैं और उनकी शहादत को कभी भुला नहीं सकते।

शहादत से एक बात आती है कि अपने प्यारे की शहादत व्यर्थ न हो। यही सबकी तमन्ना है। नवरीत 25 साल के थे। मेरा बेटा 20 साल का है। आपके भी नौजवान बेटे होंगे। लेकिन, नवरीत के साथ ऐसा हादसा हुआ कि वह वापस नहीं आए। वह क्यों गए थे, वहां कोई राजनैतिक साजिश नहीं थी, वह इसलिए गए थे, क्योंकि उनके दिल में दुख था एक पीड़ा थी। उन्हें मालूम था कि किसानों पर जुल्म हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि जुल्म करना पाप है और जुल्म सहना उस से भी बड़ा पाप है।

एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतना दूर डिबडिबा से आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचा। यह उम्मीद रखते हुए कि सभी एकत्रित होंगे तो सरकार उनकी बात सुनेगी और उनकी सुनवाई करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे भी बड़ा जुल्म तब होता है जब वे शहीदों को आतंकवादी कहते हैं। इस आंदोलन को एक राजनीतिक साजिश की शक्ल में देखते हैं। यह बहुत बड़ा जुल्म है।

राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि देश के किसान का दर्द अगर कोई सरकार नहीं देख सकती है तो वह किस काम की। नेता तो ऐसा हो जो यह कहे कि तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। आओ मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

यह मौका नहीं है राजनैतिक बात करने का, मैं यहां यह कहने आई हूं कि परिवार के दुख में शरीक हूं और इस शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कांग्रेस भी किसानों के आंदोलन में पूरी तरह साथ है, इस मौके पर उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन में हर कदम पर साथ है। रालोद के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी किसान आंदोलन का साथ देने की बात की।

गाजीपुर बॉर्डर पर 13 लेयर की बैरिकेडिंग पाक सीमा पर भी नहीं ऐसी सुरक्षा देखी..

गाजीपुर। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन गाजीपुर और सिंघु बॉर्डर पर गुरूवार के दिन भी जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करेगी। उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, विपक्षी नेताओं का 8 सदस्यीय दल किसानों से मिलने आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा। इसमें 8 राजनीतिक दलों के सांसद थे। सांसदों ने हालात का जायजा लिया। किसानों से बातचीत कर उनकी दिक्कतों को जानने की कोशिश की।

गाजीपुर पहुंचे सभी विपक्षी सांसद, अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मिलेंगे और उन्हें पूरा हाल बताएंगे। विपक्ष के सांसदों की टीम में अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके सांसद कनिमोझी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय शामिल रहे। इन सांसदों को दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल से पहले ही रोक दिया था। बाद में सांसदों ने कुछ किसान नेताओं से मुलाकात की और उनकी तकलीफों के बारें में जाना। साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

गाजीपुर बॉर्डर पर 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग लगी हुई हैं: हरसिमरत

किसान नेताओं से मुलाकात करने के बाद अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि यहां 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग लगी हुई हैं, ऐसे में किसानों की क्या हालत हो रही होगी। हमें भी यहां रोका जा रहा है हमें भी उनसे मिलने नहीं दे रहे ,13 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है, इतना तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है, हमें संसद में भी इस मुद्दे को उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सरकार को किसानों की परेशानी को समझना चाहिए। हम कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और किसान आंदोलन के समर्थन में हैं।

उपराज्यपाल का अधिकार बढ़ाए जाने पर दिल्ली और केंद्र सरकार में ठनी

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोत्तरी कर दी है उसके बाद से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में ठन गई है। बयानों और आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने कहा कि तीन बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव हार चुकी केंद्र सरकार अब पिछले दरवाजे से दिल्ली में अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे ही अड़चनें डाली जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों की व्याख्या की है उसके बाद ही दिल्ली सरकार अपने निर्णय ले पाई है। उन्होंने कहा कि अब फिर से वही सब करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली सरकार कुछ भी करना चाहेगी तो उपराज्यपाल उसमें अड़चन लगा देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अभी इस पूरे मामले का अध्ययन कर रही है, उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा।

उनका कहना है कि पहले भी कई बार उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के कई फैसले को इस तरह से रोक दिया है। 2013 में कांग्रेस की सहायता से पहली बार 49 दिन सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में तीसरी बार सत्ता में है, सभी काम ठीक तरह से चल रहे हैं ऐसे में केंद्र सरकार व्यवधान डालना चाहती है। पहले भी उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के कई अहम फैसलों में हस्तक्षेप करते हुए उसे पास नहीं किया था। जिसकी वजह से सरकार को समस्या हुई थी। एक बार पहले भी उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरना दे चुके हैं, अब अधिकारों में बढ़ोतरी किए जाने से पार्टी और खफा हो गई है। अधिकारों में बढ़ोतरी की बात पता चलते ही विरोध और बयानों का दौर शुरू हो चुका है।

तेजस्वी सूर्या ने तेजस में भरी उड़ान, कहा- लड़ाकू विमान भारत के लिए बेंगलुरु का उपहार

बेंगलुरु । कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एरो इंडिया के 13 वें संस्करण में लड़ाकू विमान गजब का करतब दिखा रहे हैं। गुरुवार को शो के दूसरे दिन यहां भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा सांसद तेजस्वी सूर्या पहुंचे। उन्होंने भारत में निर्मित तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। वह इस दौरान एयरफोर्स पायलट की ड्रेस पहने दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एलसीए तेजस आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। यह भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और क्षमताओं को बताता है। उन्होंने कहा कि वे बेहद खुश हूं कि उन्हें इस अद्भुत फाइटर जेट में उड़ान भरने का मौका मिला। एलसीए तेजस भारत के लिए बेंगलुरु का उपहार है।

बता दें कि तेजस्वी बेंगलुरु दक्षिण सीट से लोकसभा सांसद हैं। हाल ही में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के अध्यक्ष बनाए गए। एचएएल द्वारा बनाया तेजस एक इंजन वाला मल्टीरोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना को तेजस लड़ाकू विमानों से लैस करने के लिए सरकार और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच बड़ा करार हुआ है। एयरो इंडिया-2021 के उद्घाटन के अवसर पर बुधवार को 83 हल्के तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 48 हजार करोड़ रुपये के सौदे पर औपचारिक मुहर लगाई गई। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे।

तीन दिन चलने वाले इस शो के पहले दिन तेजस के साथ-साथ राफेल, सुखोई-30, जागुआर समेत अन्य लड़कू विमानों ने उड़ान भरी। इसक अलावा एचएएल के बनाए हेलीकॉप्टर, एलसीएच हेलीकॉप्टरों ने भी उड़ान भरी। सूर्यकिरण और सारंग चॉपरों ने भी शो में शामिल हुए। एक्सपो के लिए 530 से अधिक प्रदर्शकों ने पंजीकरण कराया है।

इन में से 457 भारतीय प्रदर्शक हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जापान समते 74 देशों विदेशी प्रदर्शकों ने भी हिस्सा लिया है। इनमें बोइंग कंपनी, जीई एविएशन, राफेल इंटरनेशनल, इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रूसी हेलीकॉप्टर जेएससी, यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन जेएससी, बीएई सिस्टम्स, रोल्स-रॉयस और लॉकहीड मार्टिन शामिल हैं।

राज्यसभा स्थगित, विपक्ष ने किसान आंदोलन पर केंद्र को घेरा, सरकार ने किया बचाव

नई दिल्ली । संसद का बजट सत्र जारी है। राज्यसभा में गुरुवार को विपक्षी दलों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को प्रदर्शन को लेकर सरकार को घेरा। राष्ट्रपति अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में उन्होंने मौजूदा आंदोलन से निपटने के तरीकों पर सवाल उठाए। वहीं भाजपा ने बचाव करते हुए दावा किया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी बेहतरी के लिए नए कानून लाए गए हैं। राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्तारूढ़ भाजपा ने गुरुवार को राज्यसभा में तीन नए कृषि कानूनों का बचाव करते हुए कहा कि कृषि सुधारों पर अपना रुख बदलने के लिए विपक्षी दलों पर सवाल उठाए।

वरिष्ठ भाजपा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी आय बढ़ाने के लिए पिछले छह वर्षों में कई कदम उठाए हैं। भाजपा नेता ने पिछले साल सितंबर में संसद द्वारा पारित तीन नए कृषि कानूनों पर कहा कि केंद्र ने किसान संगठनों के साथ 11 दौर की चर्चा की है। सिंधिया ने तीनों कानूनों पर रुख बदलने के लिए कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कृषि सुधारों का वादा किया था।

बता दें कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दो पालियों में आयोजित हो रही हैं। बैठकें पांच-पांच घंटे की पारी में आयोजित हो रही हैं। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह होती है और दोपहर के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है। बजट सत्र दो चरणों में आयोजित होगा। पहला चरण 15 फरवरी को खत्म होगा और दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित होगा।

राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू नई दिल्ली में संसद के चल रहे बजट सत्र के कार्यवाही दौरान।

पाकिस्तान ने अलापा शांति का राग

इस्लामाबाद। आतंकवाद को पनाह देने वाले और ताबड़तोड़ सीजफायर का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान ने शांति का राग अलापा है। सीमापार से लगातार अशांति बनाने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत को कश्मीर मुद्दे को 'गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके' से हल करना चाहिए। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का भारत द्वारा सख्त जवाब देने के बाद

पाकिस्तान रवैये में नरमी देखने को मिल रही है।

शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए जम्मू-कश्मीर मुद्दा

दरअसल, जनरल बाजवा खैबर-पख्तूनख्वा के रिसालपुर में पाकिस्तान वायु सेना के असगर खान अकादमी में स्नातक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत को जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए।

कहा- पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है

इतना ही नहीं आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। जनरल बाजवा ने कहा कि हम परस्पर सम्मान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के आदर्श पर चलने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। यह सभी दिशाओं में शांति का हाथ बढ़ाने का समय है।

कोई हमें कमजोर न समझे

हालांकि, इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि शांति की इच्छा को कोई हमारी कमजोरी न समझे। बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की सेना किसी भी खतरे को खत्म करने की क्षमता रखती है और तैयार है। खैर ये कोई पहली बार नहीं है जब जनरल कमर बाजवा ने इस तरह की गीदड़भभकी दी है।

काबुल में धमाके पर धमाके

काबुल। बड़ी खबर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ा विस्फोट हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक, राजधानी के सलीम कारवान इलाके में एक भयंकर धमाका हुआ है। हालांकि हमले में किसी के घायल होने या किसी भी तरह के जानहानि के नुकसान की सूचना सामने नहीं आई है। ये खबर स्थानीय मीडिया के हवाले से दी गई है।

गौरतलब है कि अभी भयानक विस्फोट हुआ है। ये धमाका काबुल के पीडी 10 इलाके में शहीद गोल चक्कर के पास हुआ। इस बारे में पुलिस ने जानकारी दी कि एक चुंबकीय आईईडी ब्लास्ट ने एक वाहन को निशाना बनाया। पुलिस के अनुसार, इस हादसे में भी किसी के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई।

काबुल में बढ़े तालिबानी हमले

आपको बता दें कि राजधानी काबुल में आए दिन धमाके होते रहते हैं। यहां पर सरकारी अधिकारियों, नागरिक संस्थाओं के नेताओं और पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है। ये बात ये रिपोर्ट में सामने आई है। अमेरिका के एक निगरानी समूह ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि काबुल में तालिबानी हमले बढ़ गए हैं। जिनमें सरकारी अधिकारियों, नागरिक संस्थाओं के नेताओं और पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है।

पिछली तिमाही की तुलना में बढ़े हमले

अमेरिका की ये रिपोर्ट बाइडन प्रशासन के अमेरिका-तालिबान शांति समझौते पर पुनर्विचार की योजना के ऐलान के बाद सामने आई है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी बलों के हवाले से कहा गया है कि काबुल में पिछली तिमाही के मुकाबले दुश्मनों के हमले काफी बढ़ गए हैं। बता दें कि इनमें उत्तरी बगलान और दक्षिणी उरुजगान प्रांत में दो दिन के अंदर हुए हमले भी शामिल हैं, जिसमें अफगान सुरक्षाबल के करीब 19 जवान मारे गए थे। जबकि राजधानी काबुल में एक वाहन में सवार दो लोग घायल हुए थे और एक वकील की गोली लग जाने से मौत हो गई थी।

नासा की कमान भारतवंशी को: भारतीय मूल की भव्या लाल स्पेस एजेंसी की कार्यकारी प्रमुख बनीं

वॉशिंगटन। भारतीय मूल की अमेरिकी भव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ यानी कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पेस एजेंसी में कुछ बदलाव और समीक्षा करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने भव्या को यह अहम जिम्मेदारी दी है। भव्या मूल रूप से स्पेस साइंटिस्ट हैं। वे बाइडेन की ट्रांजिशन टीम में भी रह चुकी हैं।

सोमवार रात NASA ने एक बयान में कहा- भव्या हर लिहाज से इस पद के लिए काबिल हैं। उनके पास इंजीनियरिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी का अनुभव है। वे 2005 से 2020 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के डिफेंस एनालिसिस विंग में मेंबर और रिसर्चर रही हैं। बयान में आगे कहा गया- स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी में खासा अनुभव होने के साथ उन्होंने व्हाइट हाउस में पॉलिसी और नेशनल स्पेस काउंसिल में भी काम किया है। लाल न सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बल्कि स्पेस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की भी गहरी जानकारी रखती हैं।

यूएस में 10 साल का सबसे बर्फीला तूफान

अमेरिका के 20 राज्यों में बर्फबारी; न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी में ओरलेना तूफान के कारण इमरजेंसी

वॉशिंगटन। कोरोना के बाद तूफ़ान का कहर देश में आपातकाल हालात बना रहा है। अमेरिका में भारी बर्फभारी से जनजीवन त्रस्त है। मिली जानकारी के मुताबिक, अमेरिका के पूर्वोत्तर में 'ओरलेना' तूफ़ान का संकट मंडरा रहा है। 'ओरलेना' सबसे बर्फीला तूफ़ान हैं, जो अमेरिका में 10 साल बाद आया है। भयानक बर्फबारी के चलते पूरे इलाके में आपातकाल घोषित कर दिया गया है।

अमेरिका में 'ओरलेना' तूफान का कहर

दरअसल, अमेरिका के उत्तर-पूर्वी इलाके में आपातकाल की घोषणा की गयी है। यहां लोग 10 साल के सबसे बर्फीले तूफान 'ओरलेना' का सामना कर रहे हैं। भारी बर्फबारी से पूर्वोत्तर सफेद चादर से ढक गया है। सर्द हवाएं लोगों का जीना दुश्वार किए हुए हैं।

बताया जा रहा है कि ओरलेना तूफान

के चलते यूएस में करीब 10 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और फिलाडेल्फिया में हुई बर्फबारी से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। वहीं यहां रिहाइशी इलाकों और सड़कों पर दो फुट ऊंची बर्फ की परत जम गई।

1,600 यात्री उड़ानों को रोक

ऐसी स्थिति के बाद 1,600 यात्री उड़ानों को रोकना पड़ा, जिससे कई लोग दूसरे शहरों में फंस गए है। बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क हवाई प्राधिकार ने 81 फीसदी उड़ाने तक रद्द कर दी हैं। जिसके चलते कई यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हैं।

रपोर्ट्स के मुताबिक, वाशिंगटन और बोस्टन में 10 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई है। ये बर्फबारी कई हादसो की वजह बन रही है। वहीं सैकड़ों लोग बर्फबारी से सड़क हादसे का शिकार हो रहें है। इसके अलावा 300 से ज्यादा वाहन सड़कों पर फंसकर रह गए हैं।

पड़ोसियों को डरा-धमका रहा चीन, बाइडन प्रशासन ने कहा- भारत के साथ है अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अमेरिका की सत्ता अब जो बाइडन के हाथों में है। इससे पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ सख्त रूख अपनाया हुआ था। इसके बाद अब जो बाइडन प्रशासन ने चीन सख्त नसीहत दी है।

जो बाइडन प्रशासन की तरफ से सोमवार को कहा गया है कि चीन के अपने पड़ोसियों को डराने-धमकाने के लगातार जारी कोशिशो से अमेरिका चिंतित है। इसके साथ ही प्रशासन ने कहा कि भारत-चीन सीमा के हालात पर वह करीब से नजर रख रहा है।

अमेरिका की भारत-चीन सीमा पर नजर

व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली जे होर्न ने कहा कि अमेरिका हालात पर करीब से नजर रख रहा है। भारत तथा चीन की सरकारों के बीच चल रही वार्ता की हमें जानकारी है। उन्होंने कहा कि हम

सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी वार्ता का समर्थन करना जारी रखेंगे।

चीन की इस हरकत से अमेरिका चिंतित

एमिली जे होर्न भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ कर उन पर कब्जा जमाने के चीन की कोशिशों से जुड़े हुए सवालों का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा चीन द्वारा पड़ोसियों को डराने-धमकाने के लगातार कोशिशों से अमेरिका चिंतित है। उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि, सुरक्षा एवं मूल्यों को आगे ले जाने के लिए हम अपने मित्रों, साझेदारों और सहयोगियों के साथ खड़े हैं।

सीमा पर भारत-चीन में तनाव: भारत-चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है। भारत और चीन के सैनिकों में झड़पों के संबंध में बाइडन प्रशासन ने यह पहली प्रतिक्रिया दी है। इससे पहेल भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते हफ्ते संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और कहा था कि देश के हितों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और सतर्क भी है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्यबलों की तैनाती भी की गई है। सरकार देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली ताकतों से निपटने के लिए हर स्तर पर कोशिश कर रही है।

तख्तापलट के बाद का हाल: म्यांमार में रह रहे भारतीयों को गैरजरूरी यात्रा टालने की सलाह, सेना ने सभी सीएम को रिहा किया

म्यांमार। म्यांमार में तख्तापलट के बाद सेना ने सत्ता संभाल ली है। इसके बाद बने हालात के मद्देनजर यांगून स्थित इंडियन एम्बेसी ने म्यांमार में रह रहे भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने और गैरजरूरी सफर से बचने की सलाह दी है। एम्बेसी की ओर से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। म्यांमार में इस समय लगभग 7,000 NRI रह रहे हैं। देश में भारतीय मूल के लोगों की तादाद करीब 25 लाख है। उधर, सत्ता हासिल करने के एक दिन बाद सेना ने मंगलवार को हिरासत में लिए गए रीजनल नेताओं और कई मुख्यमंत्रियों को रिहा कर दिया। हालांकि, स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और प्रेसिडेंट यू विन मिंट के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों ने बताया कि रिहा किए जाने वालों में सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के सांसद और सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। सेना के एक अफसर ने न्यूज एजेंसी शिन्हुआ को बताया कि योग्य लोगों को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है।

तख्तापलट के कुछ ही घंटे बाद तातमाडॉ नाम से जानी जाने वाली सेना ने कैबिनेट में बड़े फेरबदल की घोषणा की। इसके तहत 11 नए मंत्री नियुक्त किए गए हैं। 24 डिप्टी मिनिस्टर्स को हटा दिया गया है। सेना की ओर से आए बयान के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट-हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज पद पर बने रहेंगे। एंटी करप्शन कमीशन के मेंबर्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स भी नहीं बदले जाएंगे।

कोरोना दुनिया में: डब्ल्यूएचओ ने कहा- वैक्सीन पर राष्ट्रवादी रवैया सही नहीं, इससे वायरस ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो जाएगा

वाशिंगटन। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10.43 करोड़ से ज्यादा हो गया। 7 करोड़ 62 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 22 लाख 62 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं। WHO चीफ एडहेनोम घेब्रिसियस ने कहा है कि वैक्सीन के मामले में राष्ट्रवाद की नीति अपनाना गलत है। उन्होंने कहा कि अगर सभी देश ऐसा करने लगे तो इससे वायरस के नए म्यूटेंट्स या वैरिएंट्स बढ़ने का खतरा है।

WHO की चेतावनी

विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के डायरेक्टर जनरल एडहेनोम घेब्रिसियस ने वैक्सीन और उसको लेकर कुछ देशों के राष्ट्रवादी रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा- अगर कुछ देश 'वैक्सीन नेशनलिज्म' की नीति अपनाएंगे तो इससे खतरा बढ़ जाएगा। हमें इसे बचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे वायरस म्यूटेंट्स बढ़ जाएंगे। बहुत साफ तौर पर कहूं तो बगैर आपसी सहयोग के हम इस महामारी पर काबू नहीं पा सकेंगे।

WHO चीफ ने कहा- यह सही है कि हमारे पास वैक्सीन को लेकर ऑपशन्स बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी मानना होगा कि वैक्सीन मैन्यूफैक्चरिंग कैपेसिटी फिलहाल सीमित है। हमें ये समझना होगा कि अगर दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा वैक्सीनेशन से दूर रहता है तो इससे वायरस की ताकत बढ़ेगी। हो सकता है नए वैरिएंट्स भी सामने आएं। WHO चीफ घेब्रिसियस ने कहा है कि अगर कुछ देश 'वैक्सीन नेशनलिज्म' की नीति अपनाएंगे तो इससे खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि महामारी से मिलकर ही निपटना होगा। (फाइल)

WHO चीफ घेब्रिसियस ने कहा है कि अगर कुछ देश 'वैक्सीन नेशनलिज्म' की नीति अपनाएंगे तो इससे खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि महामारी से मिलकर ही निपटना होगा। (फाइल)

कैप्टन मूर का निधन

ब्रिटेन और दुनिया में मशहूर सेकंड वर्ल्ड वॉर के हीरो कैप्टन टॉम मूर का संक्रमण से निधन हो गया। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने उनके निधन पर शोक जताया है। कैप्टन मूर ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए लाखों डॉलर का चंदा जुटाया था। मूर 100 साल के थे। ब्रिटेन सरकार ने कैप्टन मूर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। परिवार ने कैप्टन मूर के निधन की पुष्टि की है।

कोरोना को हराने की जिद लिए टॉम ने नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए फंड जुटाने का अभियान शुरू किया था। पिछले साल 30 अप्रैल को अपने 100वें जन्मदिन से पहले उन्होंने गार्डन में 100 कदम चलकर 25 मीटर की दूरी तय की। कैप्टन टॉम ने इसके जरिए 1 हजार ब्रिटिश पाउंड (1 लाख रुपए) जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इससे उन्होंने कुल 3 करोड़ पाउंड (300 करोड़ रुपए) जुटा लिए। इसके लिए क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें नाइट की उपाधि दी थी। मेडिकल जर्नल लैंसेट ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि रूस की वैक्सीन स्पूतनिक ङ्क कोरोना से बचाव में 91.6त्न इफेक्टिव है। फेज-3 के नतीजों की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इस ट्रायल में 19,866 वॉलियंटर शामिल किए गए थे।

मिशन मार्स को झटका

स्पेस एक्स का रॉकेट लैंडिंग के दौरान क्रैश, दो महीने में दूसरी बार सेफ लैंडिंग में नाकाम

वाशिंगटन। एलन मस्क के स्पेस एक्स मिशन को दो महीने में दूसरा झटका लगा। मंगलवार को कंपनी के स्पेसएक्स रॉकेट का एक और प्रोटोटाइप लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। लौटते वक्त यह आग के गोले में तब्दील हो गया। इसके पहले दिसंबर में कंपनी का स्टारशिप रॉकेट भी इसी तरह के हादसे का शिकार हुआ था।

घटना के बाद स्पेसएक्स ने कहा- हमने एक बार फिर शानदार फ्लाइट पूरी की। हम ये मानते हैं कि लैंडिंग के मामले में हमें अभी कुछ और काम करने की जरूरत है। स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क ने मंगलवार को ही सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। मस्क ने कहा था- कुछ वक्त के लिए ट्विटर से दूर हो रहा हूं।

स्टेनलेस स्टील से बना था रॉकेट

मंगलवार को स्पेसएक्स के रॉकेट स्ह9 ने टेक्सास के बोको चिका से उड़ान भरी। स् फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे टेक ऑफ की मंजूरी देने में इस बार वक्त लगाया। दरअसल, उसे शंका थी कि स्पेसएक्स ने पिछली बार लॉन्चिंग के सभी नियमों का पालन नहीं किया था। इसलिए,

इस बार सभी नियमों का सख्ती से पालन कराया गया।

लॉन्चिंग सही तरीके से हुई। रॉकेट 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी पहुंचा। कुछ देर यह हवा में रहा। लौटते वक्त जब इसने सीधा उतरने की कोशिश की तो परेशानियां शुरू हुईं। फुटेज से साफ होता है कि लौटते वक्त उसकी रफ्तार अचानक तेज हो गई। कुछ वक्त बाद यह क्रैश हो गया। यह रॉकेट स्टेनलेस स्टील से तैयार किया गया था। ज्यादातर कम्पोनेंट हल्के थे।

दूसरी बार परेशानी

स्टारशिप ने दिसंबरमें जब SN8 रॉकेट लॉन्च किया था, तब भी लगभग यही हालात बने थे। रॉकेट की लॉन्चिंग बिल्कुल सही हुई थी, लेकिन लैंडिंग के वक्त रॉकेट बेकाबू हो गया और जमीन पर उतरने से पहले ही इसमें आग लग गई। इसके बाद स्पेसएक्स की मुश्किलें बढ़ती गईं।

उसे फिर से फ्लाइंग लाइसेंस मिलने में दिक्कत हुई, लेकिन कंपनी ने यह मसला सुलझाया और मंगलवार को फिर टेस्ट किया। हालांकि, नतीजा पिछली बार की तरह ही रहा।

सोने की जीभ: मिस्त्र में मिली 2000 साल पुरानी मम्मी

मिस्त्र। मिस्त्र की सभ्यता एक बहुत ही पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इस मिस्त्र में आज भी कई प्रकार की खोज देखने को मिलती है जिसे देख आप हैरान हो सकते हैं। आपको बता दें कि मिस्त्र में आज भी 300 ईशा पूर्व की खोज देखने को मिलती है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक ऐसी मम्मी खोजी है जिसकी जीभ सोने की है। यह बात काफी हैरान करने वाली है और काफी दिलचस्प भी है। इस मम्मी की सोने की जीभ मिलने पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। तो जानते हैं इन कयासों को।

सोने की जीभ वाली मम्मी

पुरातत्वविदों ने सोने की जीभ वाली मम्मी को मिस्त्र के तापोसिरिज मैग्ना से तलाशा है। आपको बता दें कि यह सोने की जीभ वाली मम्मी करीब 2000 साल पुरानी ममियों में से एक है। इस मम्मी की सोने की जीभ को लेकर यह मान्यता बताई जा रही है कि उस समय मरने वाला

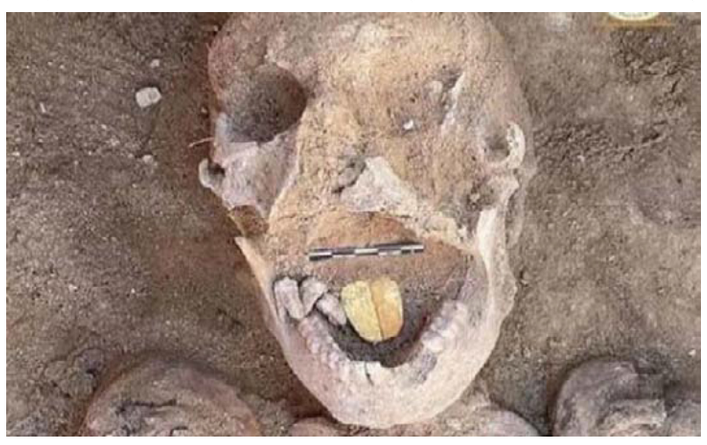

सीधे भगवान से बात करता था। इसलिए इस मम्मी की सोने की जीभ के साथ दफनाया गया था।

इस मम्मी को लेकर कोई साइंटिफिक कारण सामने नहीं आया

पुरातत्वविदों ने बताया कि इस सोने की जीभ वाली मम्मी को लेकर कोई साइंटिफिक कारण सामने नहीं आया। मिस्त्र में 2000 साल पहले इस मम्मी की जीभ सोने की क्यों बनाई इसका कोई साक्ष्य बरामद नहीं हुआ है। इस मम्मी की सोने की जीभ को लेकर मन में कई सवाल है लेकिन इसका अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इस मम्मी को लेकर कहा जा रहा कि क्या मम्मी बोल नहीं पाती थी इसलिए सोने की जीभ लगाई गई।

मिस्त्र की सभ्यता एक बहुत ही पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इस मिस्त्र में आज भी कई प्रकार की खोज देखने को मिलती है जिसे देख आप हैरान हो सकते हैं। आपको बता दें कि मिस्त्र में आज भी 300 ईशा पूर्व की खोज देखने को मिलती है।

तापोसिरिज मैग्ना में मम्मी की 16 कब्रे मिली

पुरातत्वविदों ने मिस्त्र के तापोसिरिज मैग्ना में मम्मी की 16 कब्रे खनन में मिली है। आपको बता दें कि इन 16 कब्रों में सोने की जीभ वाली मम्मी भी देखने को मिली है। इसके साथ जो 15 कब्रे मिली है जिसमें कई पुराने खजाने देखने को मिल रहे हैं। एक मम्मी मिली जो पूरी तरह से सोने से ढ़की हुई मिली है। इन ममियों में किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं दिख रहा है। इन मम्मी को देख यह कयास लगाया जा रहा है कि यह टोलेमिस शासन में रही होंगी।

पाकिस्तान में बड़ा हत्याकांड: कराची में एक लड़की समेत चार लोगों की हत्या, इनमें से तीन टिकटॉक स्टार थे

करांची। पाकिस्तान के कराची शहर में चार लोगों की कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए लोगों में तीन लड़के और एक लड़की हैं। चार में से तीन टिकटॉक पर अपने वीडियोज के लिए मशहूर थे। चारों लोग एक ही कार में सवार थे। हमलावरों ने इनका पीछा किया और कार रुकने पर करीब से गोलियां चलाईं। चारों को शहर के एक बड़े अस्पताल के सामने गोलियां मारी गईं। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

पॉश कॉलोनी में हत्याकांड

'बोल न्यूज' के मुताबिक, घटना मंगलवार को कराची की पॉश कॉलोनी गार्डन एरिया में हुई। यहां एक बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। मारे गए चारों लोग एक ही कार में सवार थे। पुलिस के मुताबिक, साजिश के तहत इन लोगों की हत्या की गई है। हमलावर काफी वक्त तक इनका पीछा करते रहे। जैसे ही अस्पताल के सामने कार रुकी। पीछे से आ रहे लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुस्कान शेख की मौके पर ही मौत हो गई। उसके तीन साथियों ने कुछ देर बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। मारे गए अन्य लोगों के नाम हैं- सद्दाम हसन, आमिर और रेहान।

पुलिस के पास सुराग नहीं

कराची के एसएसपी सिटी सरफराज नवाज ने कहा- सभी लोगों पर 9 एमएम पिस्टल से गोलियां चलाई गईं। हमने कुछ सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिए हैं। मामले की जांच तेजी से की जा रही है। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही फैसलाबाद में एक युवा की हत्या की गई थी।

एक नजर

मंदिर मार्ग पुलिस की गिरफ्त में 5 साल से फरार चल रहा घोषित अपराधी

नई दिल्ली, एजेंसी। मंदिर मार्ग थाना की पुलिस टीम ने 5 साल से फरार चल रहे एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है. इसकी पहचान गौरव अरोड़ा के रूप में हुई है जो तिलक नगर के जेल रोड स्थित आशा पार्क इलाके का रहने वाला है. डीसीपी ईश सिंघल के अनुसार, इस बदमाश ने 28 मई 2015 को नई दिल्ली के मॉडल बस्ती इलाके से कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और साथ ही कार के मालिक से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी जिसके बाद आर के पुरम पुलिस ने इसे गिरफ्तार तो किया लेकिन बेल मिलने के बाद वह फरार हो गया. इस मामले में 11 दिसंबर 2019 को पटियाला हाउस कोर्ट ने इसे भगोड़ा घोषित कर दिया था और तभी से पुलिस को इसकी तलाश थी.

मंदिर मार्ग पुलिस को इस बदमाश के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली और फिर मंदिर मार्ग थाना एसएचओ की देखरेख में सब इंस्पेक्टर जय सिंह, एएसआई इंदर सिंह और हेड कांस्टेबल चंद्र दास की टीम ने हरी नगर के आशा पार्क में छापेमारी करते हुए इसे गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई. जानकारी के अनुसार, इस पर अशोक विहार आर.के.पुरम और सरोजनी नगर थाना में 3 मामले दर्ज हैं जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

नांगलोई रेलवे स्टेशन से पीरागढ़ी तक पीडब्लूडी ने कराई सफाई

नई दिल्ली, एजेंसी। नांगलोई रेलवे स्टेशन से पीरागढ़ी तक पीडब्लूडी की टीम सफाई अभियान चला रही है, ताकि सफाई के बाद सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी न हो. नांगलोई फ्लाईओवर पर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी सफाई करने पहुंचे और फ्लाईओवर के किनारे जमी हुई मिट्टी को फावड़े से उठाकर ट्रक में भर कर सफाई की. इसी तरह पीडब्ल्यूडी के सफाई कर्मचारियों ने पूरे फ्लाईओवर से जगह-जगह जमी हुई मिट्टी को साफ किया. पीडब्लूडी के ठेकेदार ने बताया कि वह नांगलोई रेलवे स्टेशन से लेकर पीरागढ़ी तक सड़क किनारे जमी मिट्टी को साफ कर रहे हैं क्योंकि तेज हवा चलने के कारण धूल-मिट्टी उड़ने से वाहन चालकों को परेशानी होती है. उनकी आंखों में मिट्टी के कण जाने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है. वहीं सफाई कर्मचारियों का यह कहना है कि सरकार उन्हें केवल प्रतिदिन मात्र 300 रुपए का भुगतान करती है जिसमें अपना और अपने परिवार का गुजारा करने में काफी परेशानी होती है. इसलिए सरकार को पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों की प्रतिदिन की मजदूरी में इजाफा करना चाहिए ताकि उनकी परेशानियां कुछ कम हो सकें.

दिल्ली पुलिस को कंगना के खिलाफ आपराधिक शिकायत देगी जागो

नई दिल्ली, एजेंसी। ट्विटर ने आज बड़ी कार्यवाही करते हुए फिल्मी अदाकारा कंगना रनौत के विवादित ट्वीट को हटा दिया है। इस मामले में जागो पार्टी के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने कल ट्विटर के एमडी को अपने वकील के मार्फित लीगल नोटिस भेज कर कंगना का ट्विटर एकांउट बंद करने की मांग की थी। इस बारे आज ट्विटर ने अधिकारिक ब्यान जारी कर कंगना पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उसके विवादित ट्विट्स को हटाने का ऐलान किया। इस बारे जानकारी देते हुए जागो के प्रधान महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता परमिंदर पाल सिंह एवं वकील नगेन्द्र बैनीपाल ने बताया कि अब जागो पार्टी द्वारा कंगना के खिलाफ अपराधिक शिकायत दिल्ली पुलिस को देने का फैसला लिया गया है। क्योंकि ट्विटर ने कंगना के जहरीले एजेंडे को हटा करके हमारे सभी आरोपो की पुष्टि कर दी है। कंगना ने किसानों को आंतकवादी एवं अलगाववादी बताकर अपनी मुर्खता का प्रदर्शन किया है। ट्विटर ने कंगना के ट्विट्स को हटा कर किसान के आंतकवादी एवं अलगाववादी ना होने पर मुहर लगा दी है। जागो पार्टी किसी भी कीमत पर कंगना को जहर प्रचार करने की मंजूरी नहीं देगी। इस अवसर पर जागो यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हरजीत सिंह बाऊंस एवं अन्य नेता उपस्थित थे।

सरकार के पास जादुई छड़ी नहीं जो तुरंत जांच हो जाए : कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और सुरक्षा में कथित चूक की जांच की मांग वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल करते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि घटना के दो दिन के भीतर ही जांच पूरी हो जाए। क्या सरकार के पास कोई जादू की छड़ी है, जिसे घुमाते ही सब कुछ पलक झपकते हो जाएगा। न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप या तो याचिका वापस लें अन्यथा जुमार्ने के साथ इसे खारिज किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विवेक नारायण शर्मा से यह बताने के लिए कहा कि क्या उन्होंने 26 जनवरी की घटना के ठीक बाद याचिका लिखनी शुरू कर दी थी। यह याचिका 29 जनवरी को दाखिल की गई। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या आपको पता है कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच करने के लिए कितना समय दिया गया है। आप एक वकील भी हैं, बताएं कि कानून में जांच के लिए कितना समय दिया गया है। पीठ ने कहा कि आप याचिका वापस ले रहे हैं या हम जुमार्ना लगाकर खारिज करें। अधिवक्ता ने कहा कि वह याचिका वापस लेना चाहते हैं। न्यायालय ने याचिका को वापस मानते हुए खारिज कर दिया। इससे पहले सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि हिंसा को लेकर 43 मुकदमा दर्ज किया गया है।

केजरीवाल राष्ट्रविरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं-मीनाक्षी लेखी

डी.टी.सी. बसों की वापसी केजरीवाल की अराजकतावादी मानसिकता

संवाददाता

नई दिल्ली। सांसद मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था में लगी बसों को वापस लेने के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ह्यसंघ क्षेत्र दिल्लीह्न सरकार का यह फैसला देश के संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख नवीन कुमार भी उपस्थित थे।

मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केजरीवाल सरकार का यह फैसला समाजिक और आर्थिक ढांचे पर न केवल चोट पहुंचाने वाला है बल्कि राष्ट्र और समाज विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाला है। किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह की हिंसा हुई, उसे देखते हुए केजरीवाल सरकार का फर्ज था कि वह दिल्ली पुलिस के साथ हुए बस समझौते को पूरा करती। ऐसा न करके केजरीवाल देश विरोधी ताकतों के हाथों मे खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के इस फैसले में उनकी पंजाब में राजनीतिक विस्तार की मंशा काम कर रही है। सरकार का यह फैसला अराजकता को बढ़ावा देने वाला है जिससे किसी का हित नहीं होगा।

मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राघव चढ्ढ़ा से लेकर आतिशि मालेर्ना तक दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे आराजक तत्वों को पानी के टैंक पहुंचा रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली की पुलिस के साथ न देकर पंजाब के चुनाव में व्यस्त हैं। राजनीति में इतने हद तक कोई गिर सकता है, ऐसा कभी सोचा नहीं था। देश को तोड़ना इनका एकमात्र उद्देश्य है और केजरीवाल आज यही कर रहे हैं। किसानों और केंद्र के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाने की बजाय, वे कानून-व्यवस्था में व्यवधान को सुनिश्चित कर रहे हैं और साथ ही दिल्ली में अराजकता फैला रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल सरकार से सवाल किया कि आखिर लाल किले पर झंडा फहराने वालों की मदद कर दिल्ली सरकार क्या साबित करना चाहती है? इनका उद्देश्य सिर्फ दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ना है और कुछ नहीं।

एक्सपोज हो चुके हैं केजरीवाल : गौतम गंभीर

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार की दिल्ली पुलिस से बस वापस लेने के आदेश पर पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. गौतम गंभीर ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा है. सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन केजरीवाल चुप्पी साधे रहे. अब सुरक्षाकर्मियों से बस वापस ली जा रही है. आगे गंभीर ने कहा कि केजरीवाल का मकसद पंजाब चुनाव है, जिसकी वजह से वह चुपचाप हैं. दिल्ली की जनता के जज्बात से खेलकर केजरीवाल पंजाब जाना चाहते हैं. केजरीवाल दिल्ली की जनता के कंधे से पंजाब की राजनीति करना चाहते हैं. केजरीवाल इसलिए चुप हैं ताकि पंजाब चुनाव में उनका नुकसान ना हो. गंभीर ने कहा अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो चुके है.

बसें वापस मंगाने का दिया था आदेश

दिल्ली सरकार ने बुधवार को राजधानी के गाजीपुर बॉर्डर, सिंघु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर तैनात डीटीसी बसों को वापस लाने का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार को 360 बसें वापस कर दी। हालांकि पुलिस के पास अभी भी 200 से अधिक डीटीसी बसें हैं। दिल्ली सरकार ने इन्हें भी वापस करने को कहा है।

पुलिस जवानों को लेकर गई थी बसें

दिल्ली के सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 70 दिनों से अधिक समय से किसान नए कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवानों को लाने के लिए इन बलों का प्रयोग किया गया था। पुलिस को डीटीसी की ओर से 576 बसें ड्यूटी के लिए दी गई थी।

जय प्रकाश ने बालकराम अस्पताल का लिया जायजा

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने गुरूवार को कोविड-19 टीकाकरण अभियान के मद्देनजर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बालकराम अस्पताल का जायजा लिया। महापौर जय प्रकाश ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के चार अस्पताल हिन्दूराव, कस्तूरबा, गिरधर लाल व बालकराम अस्पताल में कोविड-19 टीकाकरण अभियान चल रहा है। लोग इस टीकाकरण अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे है। उन्होंने कहा कि आज देश में कोरोना के लिए टीका तैयार है और टीकाकरण के लिए लोग भी तैयार है। महापौर जय प्रकाश ने निगम के डॉक्टर, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का इस टीकाकरण अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई दी जिनके मार्गदर्शन पर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है और अब कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता साफ हो गया है। आज भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने अपनी वैक्सीन स्वयं बनाई है और हम अन्य राष्ट्रों को भी वैक्सीन उपलब्ध करवा रहें है। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए इस टीकाकरण अभियान में हम सब पूरे जोश से लगे हुए है। महापौर जय प्रकाश ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिदेशों का पूरा पालन किया जा रहा है।

दिल्ली के एक बैंक में घुसा सांप

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित एक बैंक में बृहस्पतिवार को चार फुट लंबा एक सांप आ गया जिससे अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि बेसमेंट की ओर जाने वाली सीढ़ी की रेलिंग से सांप लिपटा हुआ मिला। अधिकारियों ने तत्काल एक गैर सरकारी संगठन वाइल्ड लाइफ एसओएस को इसकी सूचना दी जिसके बाद सांप पकड़ने के दो विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे।

ड्राइवर बनकर उड़ा लेता था मालिक की कार, साथी समेत तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। कार को किराया पर चलाना एक शख्स को महंगा पड़ गया। शख्स ने कार खरीदने के बाद एक चालक को नौकरी पर रखा। एक दिन अचानक चालक ने अपना मोबाइल बंद कर दिया इसके बाद कार मालिक की लाख कोशिश के बाद भी न तो चालक को पता चला और न ही उन्हें कार वापस मिली। अंत में मामला थाना पहुंचा। शिकायत पर कार्रवाई के बाद छानबीन के दौरान पुलिस ने कार चालक का पता कर लिया। पुलिस ने न सिर्फ कार चालक बल्कि दो ऐसे लोगों को भी दबोचा जो कार के पूर्जे को अलग अलग कर उसे कबाड़ में बेच देते थे। आरोपितों की पहचान राहुल चौहान, मो. साबिर व भगत के रूप में हुई है। आरोपितों के कब्जे से कार की इंजन, सीएनजी सिलेंडर व सीएनजी किट बरामद किया गया है। कापसहेड़ा थाना में महेंद्र सिंह ने शिकायत में पुलिस को बताया कि 19 जनवरी को उन्होंने राहुल नामक शख्स को कार चालक की नौकरी पर रखा। 24 जनवरी को उन्होंने लाइव लोकेशन की जानकारी के लिए राहुल का पता लगाया तो उसका मोबाइल स्विच आफ मिला। काफी कोशिश के बाद भी जब कार नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस की शरण ली। छानबीन के दौरान पुलिस ने राहुल के संभावित ठिकानों पर ध्यान लगाया और तमाम कोशिश के बाद उसे दबोच लिया। पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को बताया कि वह कैब मालिकों से संपर्क कर नौकरी करता है।

ट्रैक्टर परेड हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट की वकील को फटकार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और सुरक्षा में कथित चूक की जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप याचिका वापस लेंगे या वह जुमार्ना लगाकर इसे खारिज करें। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और वकील विवेक नारायण शर्मा से पूछा कि क्या उन्होंने 26 जनवरी की घटना के ठीक बाद ही याचिका लिखनी शुरू कर दी थी क्योंकि इसे 29 जनवरी को दायर किया गया है।

पीठ ने वकील से पूछा, ह्यह्यआपने 26 जनवरी दोपहर को ही याचिका लिखनी शुरू कर दी थी? क्या आपको पता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच करने के लिए कितना समय दिया गया है? आप एक वकील हैं। बताएं जांच के लिए कितना समय दिया गया है?" उसने कहा कि आप चाहते हैं कि घटना के दो दिन के भीतर ही जांच पूरी हो जाए? क्या सरकार के पास कोई जादू की छड़ी है, जिसे घुमाते ही सब कुछ हो जाएगा? हम दंड लगाकर इसे खारिज करें या आप इसे वापस ले रहे हैं?" इसके बाद शर्मा ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश के तीन निवासियों की ओर से दायर की गई याचिका को वापस ले लेंगे। याचिका में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

पीठ ने कहा कि अनुमति दी जाती है। याचिका अब खारिज हो गई है क्योंकि उसे वापस ले लिया गया है।" सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि हिंसा के संबंध में 43 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और इनमें से 13 दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ (अपराध शाखा) को स्थनांतरित कर दी गई है। गौरतलब है कि केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर दो महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 जनवरी के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हो गई थी और लाल किले पर धार्मिक झंडा भी लगा दिया गया था।

अध्यक्षा और आयुक्त ने किया कालकाजी में कम्पोस्ट यार्ड का उद्घाटन

नई दिल्ली, एजेंसी। कालकाजी में गुरूवार को मध्य जोन अध्यक्षा पूनम भाटी और आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कम्पोस्ट यार्ड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूनम भाटी ने बताया कि कालकाजी में एक बड़ा कम्पोस्ट यार्ड बनाया गया है, जहां रसोई के कचरे से खाद् उत्पादित की जायेगी। इस यार्ड में 36 जालीदार कम्पोस्ट बॉक्स बनाये गये है, जिसमे जैविक खाद को बनाने के लिए अपशिष्ट कूड़े, थोड़ी मिट्टी, लकड़ी का बुरादा और पुरानी खाद को मिलाकर नई खाद बनायी जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कम्पोस्ट बॉक्स लगभग 2.5 मिट्रिक टन गीले कूड़े का निष्पादन कर सकते है। इसके अतिरिक्त इस यार्ड में नागरिकों को प्लास्टिक कचरे के बदले खाद और पौधा भी दिया जायेगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद सुनील सहदेव, अतिरिक्त आयुक्त रमेश वर्मा, उपायुक्त अवनीश कुमार व निगम के अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त ज्ञानेश भारती ने मध्य जोन के डिफेंस कॉलोनी स्थित पार्क में कम्पोस्ट साइट का निरीक्षण भी किया और जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दक्षिण निगम द्वारा कई नये कार्य किये गये, जिसमें गार्बेज कैफे, खिलौने बैंक, प्लास्टिक लाओ, खाद ले जाओ जैसे अनूठे प्रयास शामिल है। इन प्रयासो से नागरिकों की सहभागिता बढ़ेगी और वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के प्रति जागरूक होंगे व इसके महत्व को समझेंगे। उन्होंने बताया कि द.दि.न.नि. बेहतर रैंकिंग पाने के लिए विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रम चला रहा है और आर.डब्ल्यू.ए तथा मार्किट ऐसोसिएशन को भी जागरूकता व सफाई अभियानों से जोड़ रहा है। हमारी नागरिकों से अपील है कि वे इस स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग लें और रैंकिंग में सुधार लाने में हमारा सहयोग करें। इसके अतिरिक्त डिफेंस कॉलोनी, सामुदायिक भवन में आयोजित समारोह में आयुक्त और पूनम भाटी द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए चारो जोन के स्वच्छता सैनिक, कर्मचारी और आर.डब्लु.ऐ के प्रतिनिधियों को भी पुरस्कृत किया गया।

दिल्ली सरकार ने शुरू किया 'स्विच दिल्ली अभियान'

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी की सड़कों पर ई-वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार को स्विच दिल्ली अभियान की शुरूआत की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस अभियान के तहत ई-वाहनों की उपयोगिता, फायदे और पर्यावरण को होने वाले लाभ के बारे में लोगों को बताया जाएगा। लोगों से ई-वाहन खरीदने की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले छह माह में सरकार जो भी वाहन किराये पर लेगी, वह केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्लीवाले हर अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसलिए ई-वाहन की संख्या बढ़ाने के लिए हमें जन भागीदारी बढ़ानी होगी। स्विच दिल्ली अभियान में लोगों को बताया जाएगा कि वह ई-वाहन के फायदे क्या हैं। ई-वाहन के प्रयोग से प्रदूषण से कैसे निपट सकते हैं यह भी बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि बाजार एसोसिएशन, आरडब्ल्यूए, औद्योगिक क्षेत्र और खासतौर से युवा इसमें अपनी भागीदारी करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में सबसे अधिक भागीदारी वाहनों से निकलने वाले धुएं का होता है। इसलिए हम ई-वाहन को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि 2024 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले कुल वाहनों में कम से कम 25 फीसदी ई-वाहन शामिल हों।

निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरे किये जाए स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली प्रोजेक्ट के सभी कार्य : केजरीवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरूवार को अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक कर स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचआईएमएस) प्रोजेक्ट की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ स्वास्थ्य विभाग सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीएम को अधिकारियों ने प्रजेंटेशन के जरिए बताया कि एचआईएमएस प्रोजेक्ट का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और इसमें काफी प्रगति हुई है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एचआईएमएस प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार की प्रमुख प्रोजेक्ट में से एक है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस प्रोजेक्ट के सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर हर हाल में पूरा किया जाए। उल्लेखनीय है कि एचआईएमएस प्रोजेक्ट पूरा होने के साथ ही दिल्ली क्लाउड-आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली रखने वाला देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा। बैठक में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एचआईएमएस, ई-हेल्थ कार्ड और हेल्थकेयर हेल्पलाइन प्रोजेक्ट की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली एचआईएमएस को लागू करने और ई-हेल्थ कार्ड जारी करने के संबंध में विस्तार से प्रजेंटेशन दिया। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली एचआईएमएस प्रोजेक्ट के तहत एनआईटी/आरएफपी जारी कर दिया गया है। इसके लिए होने वाली प्री-बिड की दो बैठकें हो चुकी हैं और बिड जमा करने के साथ बिड का मूल्यांकन किया जा चुका है। एचआईएमएस प्रोजेक्ट के लिए वेंडर चयन की प्रक्रिया चल रही है। कोर टीम के सदस्यों द्वारा डेमो, प्रस्तुति और साक्षात्कार सहित कई पहलुओं पर विस्तृत मूल्यांकन किया जा रहा है और यह प्रक्रिया 20 फरवरी तक पूरा कर ली जाएगी। इस प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन और इसकी शुरूआत अगस्त तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसी तरह, हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट के तहत कमिटी के सदस्यों ने ईओआई के लिए एनआईटी जारी कर दिया है और ईओआई के लिए प्री-बिड बैठकें हो चुकी हैं। इसके लिए बिड जमा करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। बिड प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था, जिसमें उद्योग भागीदारों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कुल 21 रिस्पॉस मिले हैं। ओपन आरएफपी के माध्यम से वेंडर चयन और ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि हेल्थ हेल्पलाइन प्रोजेक्ट के कार्य में भी काफी प्रगति हुई है। इस प्रोजेक्ट के तहत एनआईटी/आरएफपी जारी कर दिया गया है और प्री-बिड बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। अब प्रोजेक्ट के तहत बिड जमा करने की प्रक्रिया चल रही है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार की मंसा है कि एचआईएमएस को अगस्त 2021 तक दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू कर दिया जाए। मरीजों के देखभाल की सभी सेवाएं जैसे अस्पताल प्रशासन, बजट और योजना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, बैक एंड सेवा और प्रक्रियाओं को इस सिस्टम के अंदर लाया जाएगा। ई-हेल्थ कार्ड सिस्टम के माध्यम से जारी किए जाएंगे और एक्सेस के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। डोर टू डोर सत्यापन कर भौतिक कार्ड वितरित किए जाएंगे। यह पूरा सिस्टम डिजीटल और क्लाउड पर आधारित होगी। इससे दिल्ली के लोगों को एक छत के नीचे सभी जानकारी प्राप्त करने और आपातकालीन मामलों में मदद मिल सकेगी। एचआईएमएस लागू होने के बाद दिल्ली देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा, जहां क्लाउड आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली होगी।

ई-हेल्थ कार्ड के लिए प्रस्तावित गतिविधियां : ई-हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट के तहत वोटर आईडी और जनसंख्या रजिस्ट्री के आधार पर दिल्ली के सभी निवासियों को क्यूआर कोड आधारित ई-हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। जिससे प्रत्येक मरीज की जनसांख्यिकीय और बुनियादी क्लीनिकल जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। सभी पात्रों को स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए ई-हेल्थ कार्ड के माध्यम से पूरे परिवार की मैपिंग की जाएगी। निर्बाध सूचना आदान-प्रदान के लिए दिल्ली एचआईएसएस के साथ एकीकरण किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के बाद प्रत्येक व्यक्ति को क्यूआर कोड के साथ भौतिक कार्ड वितरित किए जाएंगे। साथ ही, लोगों के अनुरोध पर संशोधित या डुप्लिकेट कार्ड जारी करने के लिए प्रावधान भी किया जाएगा।

केंद्रीकृत स्वास्थ्य हेल्पलाइन के लिए कॉल सेंटर होगा : इस स्कीम को लागू करने के लिए दो स्तर पर केंद्रीकृत कॉल सेंटर स्थापित होगा। पहले स्तर में कॉल सेंटर ऑपरेटर लोगों के कॉल और मैसेज प्राप्त करेंगे। सीआरएम को लाग-इन कर केस का आंकलन करते हुए उसका समाधान कराएंगे और संबंधित उपलब्ध हेल्थकेयर स्टाफ को बताएंगे। ऑपरेटर कॉल करने वाले को संबंधित जानकारी देंगे और अंत में उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। वहीं, दूसरे स्तर में दिल्ली सरकार के डॉक्टर और विशेषज्ञ कॉल और संदेश को प्राप्त करते हुए मरीज को मिलने का समय देंगे। यदि केस इमरजेंसी है, तो उनके कॉल को तत्काल स्वीकार करेंगे।

आंदोलन और प्रदर्शन के नाम पर हिंसक भीड़ को काबू करने की कोशिश

नई दिल्ली। आज की तारीख में कई प्रकार के राष्ट्रविरोधी तत्व सक्रिय हैं। मौके की तलाश में रहते हैं। सरकार के विरोध में कोई भी सुगबुगाहट होती है तो तुरंत चिंगारी को भड़काने में जुट जाते हैं। दरअसल ये सब सोच रहे हैं कि जैसे हजारों साल से छोटे-छोटे लोग यह सोचकर गद्दारी करते थे कि ऐसा करके दिल्ली के तख्त पर काबिज हो जाएंगे, ऐसे ही ये लोग भी सत्ता हासिल कर लेंगे, इन्हें सिर्फ सत्ता की भूख है। ये भूल रहे हैं कि प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता। लेकिन यह भी सोचने की जरूरत है कि चाहे शाहीन बाग में नागरिक संशोधन कानून के विरोध में तीन माह तक चला प्रदर्शन हो या अब दो माह से कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बार्डर को घेरे बैठे आंदोलनरत किसान।

आखिर असंतोष की चिंगारी सुलगने ही क्यों दी जाती है? उनसे समय से क्यों नहीं निपटा जाता? इनके लंबा खिंचने का ही परिणाम है कि नौकरीपेशा लोगों को मिनटों का सफर तय में करने में घंटों लगते हैं। समय और ईंधन की बर्बादी हो रही है।

हजारों करोड़ की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंच रही है। प्रदर्शन से प्रभावित इलाकों के लोगों का जनजीवन बिलकुल अस्त-व्यस्त हो गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि हर बार ऐसे आंदोलनों को बढ़ने ही क्यों दिया जाता है? मुख्य मार्गों पर आंदोलन की इजाजत ही क्यों दी जाती है? आंदोलन और प्रदर्शन के नाम पर हिंसक भीड़ को काबू करने की पुरजोर कोशिश क्यों नहीं होती? इसी की पड़ताल करना आज का मुद्दा है

संपादकीय

समता, स्वतंत्रता और न्याय पर परखें

डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सागर विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण देने आए थे। वह आठ-दस दिनों बाद ही राष्ट्रपति पद ग्रहण करने वाले थे। अपना देश गणतंत्र घोषित होने वाला था। तब मेरे पिता उस विश्वविद्यालय में अधिकारी थे, उनकी ड्यूटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देखभाल में लगी थी। भावी राष्ट्रपति सर्किट हाउस में रुके थे, जो हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं पिता के साथ चला गया। हम सर्किट हाउस पहुंचे, तो वह अपने कमरे में नहीं थे। चौकीदार ने बताया कि लॉन में बैठे हैं। हम वहां गए, तो हमने देखा कि वह अपनी बंडी के बटन कस रहे थे। जो दस दिन बाद भारत के राष्ट्रपति होने वाले हैं, वह बंडी के बटन कस रहे हैं। उन्होंने मेरे पिता को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने देखा, बटन झूल गया है। दीक्षांत समारोह में ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं इसे ठीक कर रहा हूं। मेरे मन में पहला प्रभाव यही पड़ा कि यह भारतीय गणतंत्र गांधी से चली आ रही जो सादगी है, साधारण नागरिक की जो गरिमा है, उसे पहचानने का एक तरीका या व्यवस्था बनेगा। तब स्कूलों में बहुत धूमधाम से हमने गणतंत्र दिवस मनाया था और मैंने अपनी पहली तुकबंदी भी उसी दौरान गणतंत्र की अभ्यर्थना में लिखी थी। इसके दो साल बाद जवाहरलाल नेहरू आए थे, सागर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन का शिलान्यास करने। उस शहर में परिवर्तन यह आया कि सड़कें दुरुस्त कर दी गईं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सवारी निकलनी थी। उस समय सामान्य लोगों और नेताओं के बीच दूरी बहुत कम थी। ज्यादातर नेताओं के बारे में यह संदेह भी नहीं होता था कि ये दबे-छिपे कोई गड़बड़ भी करते होंगे। एक तरह की सादगी, पारदर्शिता थी, खुला जीवन था, उनके आपस में झगड़े होते होंगे, लेकिन उनके बारे में आम धारणा यही थी कि समझदार और संवेदनशील लोग हैं। नेताओं के बारे में तब वैसी धारणा नहीं थी, जैसी अब है। उन तक अपनी बात पहुंचाना ज्यादा आसान था। जब मैं नौवीं कक्षा में था, तब विश्व-शांति को लेकर खूब चर्चा थी, एटम बम विस्फोट हुआ था। उस वक्त मैंने प्रधानमंत्री नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी कि हमें शांति के लिए प्रयत्न करने चाहिए। उनका जवाब आया कि जो मुद्दा तुमने उठाया, वह ठीक है, मगर इस वक्त तुमको अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहिए। मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमन को भी चिट्ठी लिखी थी कि आपको शांति के लिए प्रयत्न करने चाहिए। जवाब में ह्वाइट हाउस से एक बड़ा पार्सल आया, जिसमें दुनिया भर के बहुत सारे नक्शों का संग्रह था। तब के नेता लोगों की बहुत परवाह करते थे। एक अलग ही उत्साह होता था। गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों में हम लोग बहुत उत्साह से शामिल होते थे। आज लोक बदला है। लोक में संकीर्णता, घृणा भाव, भेदभाव बढ़ गए हैं। तंत्र तो मानो स्वेच्छाचार को चलाने वाली मशीन बन गया है। वैसे लोकतंत्र में लोक और तंत्र के बीच तनाव रहता है, और यह तनाव लगभग अनिवार्य है, तंत्र का काम है व्यवस्था बनाए रखना और लोक का काम है उस व्यवस्था को बदलना, तो तनाव होगा ही। हजारों किसान दो महीने से राजधानी की सीमा पर बैठे हैं, लेकिन तंत्र उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल की धारणा थी कि एक स्थाई तंत्र देश को अराजक होने से बचाएगा, एक समय तंत्र ने इस भूमिका का निर्वहन भी किया, लेकिन धीरे-धीरे वह राजनीतिक, आर्थिक रूप से भ्रष्ट हो गया। लोक से किए वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तंत्र में भी अपवाद हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन समग्रता में तंत्र में न वैसा साहस है, न वैसी सहनशीलता, वह अनेक बार गलत चीजों का बचाव करने लगता है। खासकर हिंदीभाषी अंचल में नागरिक समाज ढंग से विकसित ही नहीं हुआ। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल, असम में फिर भी नागरिक समाज है, लेकिन हिंदी समाज के ज्यादातर विश्वविद्यालय ध्वस्त हैं, ज्यादातर शैक्षणिक संस्थाएं और अध्यापक या तो राम भरोसे हैं या राज भरोसे। हिंदी समाज को कोई परवाह नहीं। क्या हिंदी इस समय धर्मांधता, घृणा, भेदभाव और झगड़े की भाषा बनकर रह गई है? हिंदी साहित्य की जो परंपरा थी, उसे आम हिंदी समाज ने मानो रौंद डाला है। आज गणतंत्र में सुधार के लिए छोटे-छोटे परिवर्तनों की जरूरत है, लेकिन यह इतना बड़ा देश है कि बड़ा परिवर्तन न हो, तो कैसे होगा, शंका स्वाभाविक है। छोटे-छोटे सत्याग्रहों से भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, न्यायिक सुधार के लिए लोक को ही आगे आना होगा। किसान आंदोलन का इस मायने में भी खास महत्व है, यह सफल हो या विफल। किसानों ने संगठित राजनीतिक तंत्र से अलग रहकर आंदोलन किया है। इस आंदोलन ने बता दिया है कि लोक अभी भी तंत्र को दबाव में ला सकता है। लोकतांत्रिक और नैतिक दबाव जरूरी है। सारी दुनिया के किसान देख रहे होंगे कि भारत के किसान क्या कर रहे हैं, जिन मुद्दों को इन किसानों ने उठाया है, वे सारी दुनिया में हैं। इसी तरह के प्रयत्न पर्यावरण, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी करने की जरूरत है। लोक अपने को फिर मजबूती से स्थापित करने के लिए समय तो लेगा। आज हर चीज का कॉरपोरेटीकरण हो रहा है। तंत्र में बैठे लोगों को क्या यह दिखाई नहीं पड़ रहा है कि अगर हमारी सार्वजनिक संस्थाएं, व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं, तो बचेगा क्या, हम सब बिकाऊ हो जाएंगे? सुधार की जरूरत है। लोकतंत्र तो अपने को लगातार संशोधित करने वाली प्रक्रिया है। और हमने संविधान को अनेक बार संशोधित किया है। संविधान की बुनियादी मान्यता है कि भारत में हर व्यक्ति नागरिक है। दूसरा, हर नागरिक को स्वतंत्रता, समता और न्याय का अधिकार है। इसे ध्यान में रखकर जांचना शुरू करें कि आखिर जो कुछ हो रहा है, क्या वह हमारी स्वतंत्रता बढ़ाता है या उसे बाधित करता है, सिकोड़ता है? जो कुछ हो रहा है, क्या वह समता फैला रहा है? क्या जो हो रहा है, वह विषमता बढ़ाकर समता को रौंद रहा है? तीसरा, न्याय के नाम पर जो हो रहा है, क्या वह न्याय है? हममें से हर एक नागरिक को इन तीन आधारों पर अपने गणतंत्र को जांचना चाहिए। वे सुधार, जो समता बढ़ाएं, जो स्वतंत्रता का भूगोल बढ़ाएं, जो न्याय को अधिक सजग, संवेदनशील, मानवीय और सच्चा बनाएं, उनका स्वागत है।

प्रवीण कुमार सिंह

जिद में तब्दील हुआ किसान संगठनों का आंदोलन, सरकार की मानेंगे नहीं और सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे नहीं

ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन तरीकों के इस्तेमाल की हर परिस्थिति में मनाही की हो। उन्होंने कहा था कि जब संवैधानिक तरीकों से हल के सारे रास्ते बंद हो जाएं तभी इनका उपयोग करना चाहिए। यह बात अलग है कि पिछले सत्तर साल से बात-बात पर आंबेडकर की दुहाई देने वालों को भी उनकी नसीहत कभी रास नहीं आई। किसान आंदोलन की मूल समस्या यह है कि आंदोलनकारी अपना हित नहीं देख पा रहे। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की पहली बैठक के बाद उसके सदस्य और शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेना किसानों के हित में नहीं है।

कुछ किसान संगठनों का आंदोलन अब उस मुकाम पर पहुंचता दिख रहा है, जहां से आगे के सभी रास्ते बंद हैं। किसानों का अब तक का रुख है कि वे सरकार की मानेंगे नहीं और सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे नहीं। उनकी मांग मानने का मतलब होगा कि बलपूर्वक और असंवैधानिक तरीकों से अपनी मांगें मनवाई जा सकती हैं। सरकार की नीतियों के विरोध से शुरू हुए आंदोलन ने धीरे-धीरे राजनीतिक शक्ल अख्तियार कर ली है। सरकार के लिए यह अब सुरक्षा और कानून व्यवस्था की भी समस्या बनता जा रहा है, खासतौर से गणतंत्र दिवस समारोह करीब होने के कारण। आंदोलनरत संगठन जो कह रहे हैं उसका निष्कर्ष यही है कि उन्हें सरकार की नीति (तीन कानूनों) पर तो बात ही नहीं करनी है। वे सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। जो बात इन तीन कानूनों में नहीं है उसकी बात हो रही है। मसलन, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था खत्म करना चाहती है, मंडियां बंद कर देगी, किसानों को कॉरपोरेट के हाथों लुटने के लिए धकेल देगी और कॉरपोरेट उनकी जमीन हड़प लेंगे। अब सरकार कोई भी हो, वह नीतियों पर तो बात कर सकती है, उनमें सुधार भी कर सकती है, मगर नीयत पर सवाल के पीछे कोई तार्किक आधार तो है नहीं। यह भावनात्मक मुद्दा है, जिसका एकमात्र आधार आशंकाएं हैं। इस आशंका शब्द में से 'आ' हटा दीजिए तो केवल 'शंका' बचती है। वही किसानों के हाथ की लाठी है। अब शंका का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, फिर भी सरकार और अब सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी इस असंभव को संभव बनाने की कोशिश कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन कमेटी बनाई, किसान संघों के वकील अदालत से गायब हो गए। जब कमेटी बन गई तो किसान संघों ने कमेटी की पहली बैठक से पहले ही मुनादी कर दी कि यह कमेटी तो हमारे खिलाफ रिपोर्ट देगी। चार सदस्यों में से एक भूपिंदर सिंह मान को तो इतनी धमकियां मिलीं कि उन्होंने कमेटी से ही तौबा कर ली। कमेटी के सदस्यों की प्रोफेशनल ईमानदारी और निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, फिर भी उठाया जा रहा है। ध्यान रहे किसान संगठनों के वकीलों की फौज में से किसी ने अपनी ओर से कोई नाम नहीं सुझाया कि यदि अदालत कमेटी बना ही रही है तो हमारी ओर से ये सदस्य होंगे। कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि ये बात न वो बात, खूंटा तो यहीं गड़ेगा।

इस पूरे मामले में एक बात समझ लेनी चाहिए कि यह पूरे देश के किसानों का आंदोलन नहीं है। यह मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा के एक हिस्से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन है, जो किसानों के हित से ज्यादा बिचौलियों की व्यवस्था बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दो वर्ग के लोग इस आंदोलन के समर्थन में हैं। एक वे, जिन्होंने कभी आंदोलन देखा नहीं। वे मुग्ध भाव और फिर सहानुभूति भाव से आप्लावित हैं। दूसरा वर्ग वह है, जिसे लग रहा है कि इस आंदोलन के सहारे वे अपनी डूबती राजनीतिक नैया को पार लगा सकते हैं। पहला वर्ग निर्दोष भाव से जुड़ा है। दूसरा वर्ग पहले पर्दे के पीछे छिपा था। अब खुलकर सामने आ गया है। मंगलवार को राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस में नया नारा दिया 'खेती का खून, तीन कानून।' उनके इस नारे से उनकी ही पार्टी के कितने लोग सहमत होंगे, कहना कठिन है, पर राहुल गांधी को इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनकी बात किसी को समझ में आ रही है या नहीं। वह अभी विदेश यात्रा से लौटे हैं तो जोश में हैं। कब तक रहेंगे, किसी को पता नहीं।

सरकार तीनों कृषि कानूनों में सुधार के अलावा इससे इतर मांगों पर भी विचार करने और उन्हें मानने को तैयार है। अन्य विपक्षी दल किसानों के साथ तो दिखना चाहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस मसले पर कांग्रेस अपना लोभ संवरण नहीं कर पाई। पार्टी की हालत नदी में डूबते हुए व्यक्ति की तरह हो गई है। उसे जो भी दिख जाए, उसी पर झपटती है।

आंदोलनकारियों का रवैया भी देखिए। सरकार का प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उनके लिए मायने नहीं रखती। वे कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। पहले सरकार ने और फिर कोर्ट ने अनुरोध किया कि मौसम और महामारी के मद्देनजर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को वापस भेज दिया जाए। जवाब था-नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण कदम उठाते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कानूनों के अमल पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसका भी किसानों पर असर नहीं पड़ा। अब गणतंत्र दिवस की परेड के समानांतर परेड की जिद पर अड़े हैं। पुलिस कह रही है दिल्ली से बाहर कर लीजिए। जवाब है-नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस को अधिकार है कि वह रैली की इजाजत दे या नहीं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम संबोधन में कहा था, 'सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संवैधानिक उपाय उपलब्ध हों तो असंवैधानिक तरीकों का उपयोग 'ग्रामर ऑफ एनार्की' है। इनसे जितनी जल्दी मुक्ति पा लें उतना अच्छा।' उनके मुताबिक हिंसक क्रांति, सिविल नाफरमानी, असहयोग और सत्याग्रह असंवैधानिक उपाय हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन तरीकों के इस्तेमाल की हर परिस्थिति में मनाही की हो। उन्होंने कहा था कि जब संवैधानिक तरीकों से हल के सारे रास्ते बंद हो जाएं तभी इनका उपयोग करना चाहिए। यह बात अलग है कि पिछले सत्तर साल से बात-बात पर आंबेडकर की दुहाई देने वालों को भी उनकी नसीहत कभी रास नहीं आई।

किसान आंदोलन की मूल समस्या यह है कि आंदोलनकारी अपना हित नहीं देख पा रहे। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की पहली बैठक के बाद उसके सदस्य और शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेना किसानों के हित में नहीं है। यदि इन कानूनों को वापस ले लिया जाता है तो अगले पचास साल तक कोई सरकार कृषि सुधार का प्रयास नहीं करेगी। किसानों का एक ही जवाब है-हम तो नहीं मानेंगे, कर लो जो करना हो।

मध्य प्रदेश में दिग्गी राजा की दुविधा से कांग्रेस को न माया मिली और न राम

दिग्गी राजा यानी मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम नेता दिग्विजय सिंह। निजी और राजनीतिक जीवन में उनके नाम कई ऐसे कीर्तिमान दर्ज हैं जिनके बारे में अधिकतर नेता सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस की प्रादेशिक और राष्ट्रीय राजनीति में दिग्गी राजा को कई अच्छी-बुरी बातों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उनकी उम्र काफी हो चली है, पर अब भी हर दिन भरपूर सक्रिय रहते हैं और अपनी अलग शैली में कुछ न कुछ नया किया करते हैं। उनका सबसे ताजा कारनामा है, अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग धनराशि का चेक श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पते पर भेजना। दिग्गी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में कई अहम भूमिकाओं में रह चुके हैं। उनके लिए यह समझना कतई कठिन नहीं है कि राम मंदिर निर्माण की सहयोग राशि प्रधानमंत्री को भेजना कितना बेतुका एवं हास्यास्पद है। श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट गठित है। देशभर से प्राप्त हो रही सहयोग राशि इसी ट्रस्ट के खाते में जमा हो रही है। आम श्रद्धालुओं की तरह लाखों कांग्रेसी भी इसी ट्रस्ट के खाते में सहयोग राशि जमा कर रहे हैं, पर दिग्गी राजा तो दिग्गी राजा ठहरे। वह भला आम आदमी की तरह क्यों सोचें?

वह आम आदमी की तरह सोचने लगेंगे तो कांग्रेस की मौजूदा हालत और खुद उनकी उम्र-आधारित परिस्थितियों के बीच उनकी क्या प्रासंगिकता रह जाएगी? इसलिए राजा साहब ने अपना चेक प्रधानमंत्री को भेज दिया। इसके पीछे उनके अपने तर्क होंगे, पर उनके इस कृत्य पर आम आदमी के अपने सवाल हैं। यक्ष प्रश्न यह है कि राम को काल्पनिक पात्र बताने वाली पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता को राम मंदिर निर्माण में सहयोग

करने की जरूरत क्यों महसूस होने लगी? ज्यादा वक्त नहीं हुआ। प्रियंका गांधी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने अयोध्या गई थीं, पर रामलला का दर्शन करने नहीं गईं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उन नेताओं में शुमार हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप जड़ते रहे हैं। वह राम मंदिर आंदोलन को भी राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं।

मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता भी सवाल उठा रहे हैं कि दिग्गी राजा द्वारा मंदिर निर्माण की सहयोग राशि का चेक प्रधानमंत्री को भेजना क्या राजनीति नहीं है? वह इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, पर आम आदमी उनकी स्वीकारोक्ति का इंतजार नहीं करता। सबको दिख रहा है कि राजा साहब राम मंदिर निर्माण में भी नकारात्मक राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। जब उनके कद का नेता ऐसी हरकत करता है तो उसका खामियाजा पार्टी को भी भुगतना पड़ता है। कांग्रेस पहले ही बहुत कुछ भुगत रही है। दिग्गी राजा जाने-अनजाने उसके भविष्य को भी अभिशप्त करवा रहे। मध्य प्रदेश के तटस्थ लोग इस बात पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हिंदू आतंकवाद जैसा जुमला इसी प्रदेश के कांग्रेसी नेता ने गढ़ा। सनातन धर्म के संतों और धर्माचार्यों के बारे में सर्वाधिक अपमानजनक टिप्पणियां यहां के कांग्रेस नेताओं ने ही कीं। पार्टी इसका खामियाजा भी भुगत रही है, पर दिग्विजय सिंह जैसे नेता अब भी इन सबसे सबक सीखने को तैयार नहीं।

राम मंदिर निर्माण के लिए मध्य प्रदेश समेत पूरे विश्व में उल्लास हिलोरे ले रहा है। अमीर-गरीब अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक योगदान करके धन्य महसूस कर रहे, पर दिग्विजय सिंह अब भी इसे लेकर राजनीति में उलझे हैं। उनके मन में राम मंदिर के प्रति रंचमात्र आस्था होती तो वे ऐसी हल्की हरकत न करते, पर वह अपनी सोच और आदत से लाचार हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश राम मंदिर निर्माण के लिए बढ़-चढ़कर सहयोग करने वाला प्रदेश है। यहां के मुसलमान भी दिल खोलकर धनराशि समर्पित कर रहे हैं, पर दिग्विजय सिंह को भ्रम हो रहा कि राम मंदिर निर्माण के प्रति सच्ची आस्था दर्शाने से उनका वोटबैंक लुट जाएगा। मध्य प्रदेश में उनके पास कहां वोटबैंक बचा है? उनकी दुविधा से कांग्रेस को न माया मिली और न राम।

वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में किसानों से कर्जमाफी का झूठा वादा करके कांग्रेस अपना रहा-बचा आधार भी गंवा चुकी। राम मंदिर निर्माण में सच्चे मन से सहयोग करके पार्टी अपना प्रायश्चित शुरू कर सकती थी, पर राजा साहब ने अपनी स्मार्टनेस से यह अवसर भी छीन लिया। हर स्तर के देशवासियों के सहयोग से अयोध्या में कुछ ही वर्षों में दुनिया का भव्यतम धर्मस्थल बनकर तैयार हो जाएगा, पर इसके निर्माण के इतिहास में कांग्रेस को दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की निम्नस्तरीय हरकतों के अलावा अपना कोई योगदान नहीं दिखेगा।

वायरस की लुकाछुपी

देश में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को सशर्त मंजूरी मिले एक महीना बीत चुका है। 3 जनवरी को सरकार ने ऑक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सिन टीकों को मंजूरी दी थी। हालांकि टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से हुई, फिर भी भारत सबसे ज्यादा तेजी से 40 लाख लोगों को टीका देने वाला देश बन गया है। इस बीच टीके के मोर्चे पर कुछ और उत्साह बढ़ाने वाली खबरें आई हैं। रूस में निर्मित वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर शुरू में कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं। इसकी मुख्य वजह थी तीसरे फेज की ट्रायल रिपोर्ट का न आना। मगर अब फील्ड रिपोर्ट आ गई है और इस टीके की कार्यकुशलता 91.6 प्रतिशत बताई जा रही है। हालांकि अमेरिकी कंपनियों मॉडर्ना और फाइजर के टीकों के मामलों में यह आंकड़ा 94 फीसदी पाई गई है, लेकिन स्पुतनिक वी की एक विशेषता उसकी कम लागत भी है। मॉडर्ना और फाइजर के मुकाबले स्पुतनिक वी की कीमत करीब एक तिहाई पड़ती है, जो गरीब देशों के लिए बड़े काम की सूचना है।

भारत में दिए जा रहे टीके कोविशील्ड और कोवैक्सिन सस्ते तो हैं, लेकिन उनकी कार्यकुशलता को लेकर अभी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है। टीके का दूसरा डोज पड़ जाने के बाद ही जाना जा सकेगा कि जमीनी तौर पर ये कितने कारगर साबित होते हैं। बहरहाल, स्पुतनिक वी की कामयाबी भारत के लिए भी अहम है। सस्ते और कारगर टीकों की जरूरत यहां इतने बड़े पैमाने पर पड़ने वाली है कि एक-दो टीके काफी नहीं होंगे, हालांकि कोरोना के नए मामलों की संख्या में कमी से फिलहाल थोड़ी राहत जरूर है। यह राहत देश ही नहीं, दुनिया के स्तर पर भी दिख रही है लेकिन इस वायरस के प्रकोप की लहर पीछे जाकर दोबारा ज्यादा वेग से लौटने के कई उदाहरण पेश कर चुकी है। ताजा मामला ब्रिटेन का है जहां न केवल कोरोना के मामले बिल्कुल नीचे जाने के बाद अचानक बढ़ गए बल्कि वायरस के एक नए रूप का आतंक वहां कोरोना की शुरुआत से भी ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रसंग में एक और बात उल्लेखनीय है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (शरीर की श्वेत रक्त कणिकाओं की क्लोनिंग करके बनाई गई एंटीबॉडी), जिसकी चर्चा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के इलाज के बाद काफी हुई थी, वायरस के नए रूपों के लिए व्यर्थ है। ब्रिटेन और अफ्रीकी देशों में दिखे नए वायरस वैरिएंट्स से जुड़े मामलों में इलाज की इस पद्धति को नाकारा पाया गया। साफ है कि इस वायरस ने इंसानों के साथ लुकाछुपी का जो खेल शुरू किया है उसका तुरत-फुरत निपटारा मुश्किल है। भले ऐसा लगे कि अब तो कई सारे टीके आ गए हैं और नए मामलों की संख्या भी कम हो गई है, पर इसके पलटवार की संभावना अभी ज्यों की त्यों है। इसीलिए इस बीमारी का सफाया होने तक न तो इससे लड़ाई में कोई ढील बरती जा सकती है, न ही बचाव से जुड़ी सावधानियां कम करने का जोखिम उठाया जा सकता है।

श्रम सुधारों की दिशा में सार्थक पहल, असंगठित क्षेत्रों के कामगारों और उनके परिवारों की ली गई सुध

ऐसे में इस वर्ग की आय में बढ़ोतरी मांग को बढ़ावा देगी। यानी श्रम सुधार इन निम्न मध्यम आय वाले परिवारों के लिए घरेलू आय में वृद्धि करके मांग को बढ़ावा देगा और मांग बढ़ने से जीडीपी में वृद्धि होगी। जब सरकार किसी कंपनी को कर छूट देती है तो वह तत्काल निवेश या खर्च में तब्दील नहीं होता, लेकिन किसी कामगार को 500 रुपये भी अतिरिक्त मिलता है तो वह कुछ जरूरत की नई चीजें खरीदना चाहता है, जो तत्काल मांग पैदा करता है।

कृषि कानूनों पर राजनीति से प्रेरित आंदोलन इन दिनों सुर्खियों में है। इस बीच केंद्र सरकार ने समग्र दृष्टिकोण के साथ एक क्रांतिकारी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार ने सभी पक्षों के साथ व्यापक विमर्श कर श्रम सुधारों की पहल की है। पहली बार किसी सरकार ने संगठित के साथ असंगठित क्षेत्रों के कामगारों और उनके परिवारों की सुध ली है। इसके साथ ही नौकरी देने और पाने वालों के संबंधों को एक परिवार भाव में पिरोने की कोशिश की है। इसे दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत के तहत आगे बढ़ाया है। श्रम सुधार कानून का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को निश्चित वेतन, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और पेंशन की सुरक्षा के दायरे में लाना है।

इन सुधारों से अब हर क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर और डिलीवरी ब्वॉय से लेकर मैनेजर और इंजीनियर तक सबको सम्मान के साथ आर्थिक न्याय मिल पाएगा। देश में 29 करोड़ परिवार और सभी क्षेत्रों में काम करने वालों को मिलाकर 55 करोड़ श्रम बल है। इसमें 60 फीसद काम करने वाली आबादी यानी करीब 30 करोड़ लोग गैर कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। श्रम सुधार सीधे इन 30 करोड़ लोगों पर सकारात्मक असर डालेगा। देश के करीब 13-15 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होंगे। इस लिहाज से देश का हर दूसरा परिवार इन सुधारों से प्रभावित होगा। चार श्रम कानूनों के माध्यम से अब राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा। सभी कामगारों को हर

महीने की सात तरीख से पहले बैंक ट्रांसफर से वेतन उपलब्ध कराने की मुहिम चलेगी। पुरुष एवं महिला मजदूरों को समान वेतन देना अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर 13-15 करोड़ निम्न मध्यमवर्गीय भारतीय परिवारों का जीवन स्तर और मौजूदा आमदनी बढ़ेगी।

सभी कामगारों को सुरक्षा दिलाने के मकसद से केंद्र सरकार ने नौ श्रम कानूनों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोड से जोड़ दिया है, ताकि श्रमिकों को बीमा, स्वास्थ्य चिकित्सा, बोनस, पेंशन, मातृत्व लाभ आदि के अधिकार सुरक्षित हो सकें। श्रम सुधार कानूनों में फैक्ट्रियां, रिटेल शो रूम, रेस्तरां, ई-कॉमर्स डिलीवरी, खनन, कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, मोटर ट्रांसपोर्ट से लेकर संविदा श्रमिक और अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर सभी के हितों को सुनिश्चित किया गया है। सरल भाषा में कहा जाए तो बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनी के मैनेजर से लेकर डिलीवरी ब्वॉय तक सभी कामगार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में समान रूप से आएंगे। साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति भी इस मूलभूत सुविधा से वंचित नहीं होगा।

पहले श्रम कानूनों में कई प्रविधान अंग्रेजी राज के थे। इससे सभी क्षेत्रों में काम करने वाले कामगार और काम देने वाले नियोक्ता, दोनों के हितों की रक्षा के बजाय उन्हें परेशानियों का ही सामना करना पड़ता था। कानूनों का जाल ऐसा था कि एक ही काम के लिए कामगार को कई फॉर्म भरने पड़ते थे तो कंपनियों को तमाम धाराओं और अन्य बिंदुओं में बंटे 44 कानूनों की वजह से श्रम विभाग के दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते थे। ऐसे में बेकार कानूनों को मौजूदा सरकार ने रद किया और अब सभी श्रम कानूनों को चार कोड में समाहित किया जा रहा है। श्रम सुविधा के पोर्टल के जरिये उद्योगों को भी ऑनलाइन और फेसलेस रिटर्न की व्यवस्था की गई है। उद्योग जगत को मिली सहूलियत से लाखों घंटे मानव श्रम की बचत होगी। इतना ही नहीं, इससे श्रम विवादों की संख्या कम होगी। कारोबारी सुगमता से भारत की रैंकिंग सुधरेगी और विदेशी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दुनिया में भारत 148वें पायदान पर है। ऐसे में जरूरत है कि बेरोजगारी के साथ कम वेतन की समस्या को दूर करने पर काम भी हो। श्रम सुधार इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हैं, जो न सिर्फ रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, बल्कि पूरी सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ सुनिश्चित वेतन- भत्ते से हर नौकरीपेशा का जीवन स्तर भी बेहतर होगा। इस नए फ्रेमवर्क में लैंगिक भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करते हुए महिला-पुरुष के लिए समान वेतन निर्धारित किया गया है। मैन्यूफैक्चरिंग ही नहीं, सेवा क्षेत्र से लेकर निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में भी यह लागू होगा। साथ ही नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करेगा।

घरेलू उपभोग हमारी कुल अर्थव्यवस्था (जीडीपी) का करीब 60 फीसद है। यानी निवेश, सरकारी खर्च और कुल आयात-निर्यात को छोड़ दें तो यह जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने के लिए आवश्यक है कि घरेलू मांग और खपत को बढ़ावा दिया जाए। इस दिशा में श्रम सुधार सबसे अहम है, क्योंकि इससे घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी और उपभोग की क्षमता बढ़ेगी। अभी देश के 29 करोड़ परिवारों में से 13-15 करोड़ परिवारों की आमदनी 1.5 लाख से 3.5 लाख रुपये के बीच है। आने वाले वर्षों में इसमें 20-30 फीसद की वृद्धि होगी। ऐसे में इस वर्ग की आय में बढ़ोतरी मांग को बढ़ावा देगी। यानी श्रम सुधार इन निम्न मध्यम आय वाले परिवारों के लिए घरेलू आय में वृद्धि करके मांग को बढ़ावा देगा और मांग बढ़ने से जीडीपी में वृद्धि होगी। जब सरकार किसी कंपनी को कर छूट देती है तो वह तत्काल निवेश या खर्च में तब्दील नहीं होता, लेकिन किसी कामगार को 500 रुपये भी अतिरिक्त मिलता है तो वह कुछ जरूरत की नई चीजें खरीदना चाहता है, जो तत्काल मांग पैदा करता है। निश्चित तौर से नए भारत के नए श्रम कानून देश के श्रम जगत को सही मायने में सामाजिक-आर्थिक न्याय दिलाने और केंद्र सरकार के न्यू इंडिया के संकल्प को साकार करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम बनने वाला है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

उत्पाद विभाग की उदासीनता: झारखंड-ओडिशा पहुंच रहा गांजा, शराब तक ही सीमित रह गया महकमा

डोभी (गया)। झारखंड और उड़ीसा से गांजा की सप्लाई बिहार सहित कुछ और राज्यों में होती है। इसके लिए सुगम सडक मार्ग है, जो गया के बाराचट्टी और डोभी होकर गुजरती है। इस अवैध कारोबार के इस कार्य में लगे माफिया को माल समेत कई थाना को गुजरना पड़ता है। चौकन्ना रहने वाला थाना को माफिया वर्ग के द्वारा मैनेज किया जाता है। समेकित जांच चौकी डोभी पर उत्पाद विभाग के लिए भी कार्यालय और गार्ड की व्यवस्था की गई है। शराबबंदी के पहले उक्त स्थान पर उत्पाद विभाग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती थी। परंतु जब से सूबे में शराबबंदी की घोषणा हुआ तब से इस चेकपोस्ट पर तीन-चार सब इंस्पेक्टर और दो दर्जन से ज्यादा गार्ड की व्यवस्था जांच के लिए विभाग ने कर रखा है। फिर भी इस चेकपोस्ट से प्रतिदिन दर्जनों शराब और महुआ फूल से लदी गाड़ी आसानी से पार हो जाती है। जिसमें कई वाहन की जानकारी अधिकारी को होती है परन्तु इसे नही पकड़ा जाता है। गांजा का कारोबार मुख्यतः जीटी रोड से ही होता है। इस कार्य मे उपयोग किया जाने वाला गाड़ी महंगी और लक्जरी होती है, जिसे उत्पाद विभाग के अलावे अन्य लोगों को शक भी नही हो सकता है। वर्तमान के चेकपोस्ट पर तीन सब इंस्पेक्टर की तैनाती है। सूत्र की मानें तो प्रत्येक माह पचास करोड़ का गांजा और कई करोड़ का शराब और महुआ फूल का कारोबार हो रहा है।

अलीगढ़ मुस्लिम विवि के पूर्व छात्र नेता शरजील उस्मानी पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

लखनऊ । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता शरजील उस्मानी के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में बुधवार देर रात धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंस्पेक्टर हजरतगंज श्यामबाबू शुक्ला ने बताया बताया कि मुकदमा कृष्णानगर रामगढ़ कालोनी निवासी अनुराग सिंह ने दर्ज कराया है। आरोप है कि 30 जनवरी को शरजील उस्मानी ने महाराष्ट्र में एल्गार परिषद के सम्मेलन में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काने की मंशा से विवादित और भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया था। जिससे विद्वेष फैल सकता है। लोगों में शत्रुता होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल हो सकता है। इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। अनुराग सिंह से छात्र नेता के बयान की वीडियो सीडी भी ली गई है। साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। अनुराग सिंह ने बताया कि शरजील उस्मानी का भड़काऊ बयान सोशल मीडिया और यू-ट्यूब पर भी वायरल हो रहा है। उसके बयान से धर्म विशेष में घृणा पैदा कर हो सकती है। सरजील के इस कृत्य से समाज के लोगों में आक्रोश भी है। अनुराग ने शरजील के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है।

मुरादाबाद में मामूली विवाद में नर्यातक से मारपीट, तीन लोग हरिासत में

मुरादाबाद । नागफनी थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर कुछ युवकों ने निर्यातक के साथ मारपीट की। बचाव में आए चौकीदार को भी युवकों ने पीट दिया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, वहीं निर्यातक ने चेन लूटने का आरोप लगाया है।

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रामगंगा विहार निवासी तरुण महाजन की नागफनी के दसवां घाट के पास निर्यात फर्म है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग फर्म के बाहर खड़ी कार को नुकीली चीज से खुरच रहे थे। सुरक्षा गार्ड राजवीर ने जब विरोध किया तो उसके साथ युवक गाली-गलौज करने लगे। गार्ड ने जब मालिक को जानकारी दी तो वह बाहर आकर युवकों से बात करने लगे। इतने में ही आठ से दस युवकों ने उन पर हमला कर दिया। निर्यातक ने आरोप लगाया कि इस दौरान हमलावर युवक सोने की चेन और डायमंड की अंगूठी भी लूट ले गए। सूचना मिलने मौके पर थाना पुलिस पहुंची। इस दौरान फर्म में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस ने तीन आरोपित युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। नागफनी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि किसी भी पक्ष के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।

हरदोई में घर के बाहर से लापता हुआ था मासूम, 20 दिन बाद मिला बोरी में मिला शव

हरदोई । कोतवाली देहात क्षेत्र के कौढ़ा गांव से 15 जनवरी की शाम से लापता बच्चे का शव गांव के बाहर बोरी में मिला। शव मिल की सूचना पर सनसनी फैल गई और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस और आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल की। ग्राम कौढ़ा निवासी मायाराम लुधियाना में मजदूरी करते हैं। उनकी पत्नी तीन बच्चों के साथ गांव में रहती है। 15 जनवरी की शाम उनका छह वर्षीय पुत्र गोलू घर के बाहर जल रही आग के पास बैठा था। कुछ देर बाद मां बुलाने गई तो वह गायब था। घरवालों को जानकारी हुई तो खलबली मच गई। पूरी रात तलाश होती रही, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। गुरुवार की सुबह बच्चे का शव गांव के बाहर बोरी में बंधा मिला। ग्रामीणों ने शव को देखा और परिवार को जानकारी दी, जिसके बाद वह लोग मौके पर पहुंच गए और चीख पुकार मच गई। एएसपी पूर्वी अनिल कुमार, सीओ सिटी विकास जायसवाल, कोतवाल उमाशंकर उत्तम और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं।

सकारात्मक सोच और संयमित जीवनशैली से समस्तीपुर के प्रो. रामभरत ठाकुर ने कैंसर को दी मात

दलसिंहसराय (समस्तीपुर) । आत्मबल और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कैंसर जैसी बीमारी को मात देने वाले दलसिंहसराय के प्रो. रामभरत ठाकुर इसकी मिसाल हैं। अब सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समय-समय पर चेकअप कराते रहते हैं। डॉक्टर की सलाह पर संयमित जीवनशैली अपना ली है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष रहे दलसिंहसराय निवासी प्रो. रामभरत ठाकुर को जून, 2018 में पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है। यह पूरे परिवार के लिए सदमे वाली सूचना थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। स्थानीय स्तर पर इलाज चला। इसके बाद दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में गए। मार्च 2019 में इस बीमारी से मुक्त हुए। अभी हर छह महीने पर जांच के लिए जाते हैं। डॉक्टरों की बताई हर बात का पालन करते हैं। सुबह योग से उनकी दिनचर्या शुरू होती है। संयमित जीवनशैली अपना ली है। वेबिनार सहित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। कैंसर के प्रति जागरूक करते हैं। प्रो. ठाकुर कहते हैं कि जब उनकी बीमारी की बात सार्वजनिक हुई तो कई अपनों ने भी दूरी बना ली थी। हालांकि, घरवाले हौसला बढ़ाते रहे। लोगों को बताता हूं कि कैंसर पीड़ित से दूरी नहीं, नजदीकी बढ़ाएं। उन्हें हौसला दें। दवा के साथ लोगों का अपनापन वरदान साबित होता है।

जालंधर में महाजन सभा ने लेखन प्रतियोगिता व कार्यकारिणी कमेटी की बैठक करवाई, वर्चुअल शामिल हुए सदस्य

जालंधर । जालंधर में महाजन सभा की तरफ से लेखन प्रतियोगिता तथा कार्यकारिणी कमेटी की बैठक हुई। सभा के अध्यक्ष अजय महाजन की अध्यक्षता में आयोजित प्रतियोगिता में देश भर में महाजन सभा के सदस्य वर्चुअल शामिल हुए। महासचिव केएल महाजन ने बैठक का संचालन किया। डॉक्टर रानू गुप्ता ने महाजन सभा द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। सरोज महाजन व स्वर्ण महाजन ने विचार रखे। हिमांशु महाजन व उषा महाजन ने ऑनलाइन प्रोजेक्ट की मेजबानी की।

अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर विवाद, पांच एकड़ भूमि पर दो महिलाओं ने किया दावा

लखनऊ । इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में बुधवार को एक रिट याचिका दाखिल कर अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद बनाने के लिए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित कुल 29 एकड़ जमीन में से पांच एकड़ को विवादित बताया गया है। याचिका दिल्ली की रानी कपूर पंजाबी व रमा रानी पंजाबी की ओर से दाखिल की गई है। इस पर आठ फरवरी को सुनवाई संभावित है। याचिका दायर कर दोनों महिलाओं ने आवंटित जमीन मे से पांच एकड़ पर अपना हक होने का दावा किया है। साथ ही यह भी कहा है कि उक्त पांच एकड़ की जमीन के संबंध में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष एक मुकदमा विचाराधीन है।

याचियों का कहना है कि बंटवारे के समय उनके माता-पिता पाकिस्तान के पंजाब से आए थे। वे फैजाबाद (अब अयोध्या) जनपद में ही बस गए। बाद में उन्हें नजूल विभाग में ऑक्शनिस्ट के पद पर नौकरी भी मिली। उनके पिता ज्ञान चंद्र पंजाबी को 1,560 रुपये में पांच साल के लिए ग्राम धन्नीपुर, परगना मगलसी, तहसील सोहावल, जनपद फैजाबाद में लगभग 28 एकड़ जमीन का पट्टा दिया गया। पांच साल के पश्चात भी उक्त जमीन याचियों के परिवार के ही उपयोग में रही व याचियों के पिता का नाम आसामी के तौर पर उक्त जमीन से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। हालांकि, वर्ष 1998 में सोहावल एसडीएम द्वारा उनके पिता का नाम उक्त जमीन से संबंधित रिकॉर्ड से हटा दिया गया, जिसके विरुद्ध याचियों की मां ने अपर आयुक्त के यहां लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी व उनके पक्ष में फैसला हुआ।

याचियों का कहना है कि अपर आयुक्त के आदेश के बाद भी चकबंदी के दौरान पुनः उक्त जमीन के राजस्व रिकॉर्ड को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ।

तब चकबंदी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष मुकदमा दाखिल किया गया, जो अब तक विचाराधीन है। याचियों का कहना है कि मुकदमा अब तक विचाराधीन होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा इसी जमीन में से पांच एकड़ भूमि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित कर दी गई है। याचियों ने आवंटन व उसके पूर्व की संपूर्ण प्रक्रिया को चुनौती दी है।

रामपुर पहुंचीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका वाड्रा, बलिासपुर में कार्यक्रम में होंगी शामलि

मुरादाबाद । कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका वाड्रा गुरुवार को रामपुर पहुंचीं। वह बिलासपुर के डिबडिबा गांव में किसान नवरीत सिंह के भोज कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचीं हैं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत कयिा। राष्ट्रीय महासचिव के साथ कसिान नेता राकेश टकैत के बेटे गौरव टकैत भी हैं।

रामपर के कसिान नवरीत की गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान मौत हो गई थी। प्रियंका वाड्रा के कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया। खुफिया तंत्र भी एक्टिव हो गया है। कांग्रेस नेताओं से प्रशासन संपर्क कर जानकारी लेता रहा। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने बताया कि अभी तक उन्हे कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है। लेकिन, जानकारी में आया है कि उनके आने का कार्यक्रम है।

मुरादाबाद के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिले की सीमा पर स्वागत के लिए खड़े रहे। पूर्व सांसद बेगम नूरबानो, पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, कांग्रेस नेता बबलू खां, मामून शाह खां, बाबर खां, धर्मेंद्र गुप्ता आदि उनके आने की राह देखते रहे। काफलिा दखिाई देते ही कांग्रेसी स्वागत के लिए दौड़ पड़े।

सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त-मुरादाबाद में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। मुरादाबाद की सीमा से लेकर रामपुर की सीमा तक पुलिस बल की तैनाती की गई है। ताकि रास्ते में दोनों नेताओं की सुरक्षा में कोई चूक न हो। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि मुरादाबाद में कोई कार्यक्रम नहीं है। फिर भी सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में एक और वाद दायर, चौथे केस की सुनवाई

मथुरा । भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में एक अन्य वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल किया गया है। इस मामले में सुनवाई गुरुवार को होगी।

श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन को लेकर के यहां के ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव के सेवायत ने सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनौदिया की कोर्ट में एक और दावा दायर किया है। दावा 2 फरवरी को दायर किया गया। अदालत में बहस न होने के कारण इस दावे पर सुनवाई के लिए 4 फरवरी यानि आज की तारीख तय कर दी है। उन्होंने भक्त की हैसियत से वाद दायर कर यहां श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी 13.37 एकड़ भूमि श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को देने की मांग की है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई के लिए तिथि तय की गई है।

ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव के सेवायत पवन कुमार शास्त्री मलपुराश्री कृष्ण जन्म स्थान के निकट के रहने वाले हैं। 24 दिन में एक दिन उनकी मंदिर में सेवा आती है। उन्होंने अपने केस में इंतजामियां कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मथुरा के प्रबंधक श्रीकृष्णा जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव को पार्टी बनाया गया है। उनके अधिवक्ता आर एस भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने अदालत से 13.37 एकड़ भूमि से कब्जा हटाने की मांग की गई है। उन्होंने इसके लिए कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का शुरू से लेकर आखिर तक का इतिहास पेश किया है।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में पहले से तीन वाद अदालत में चल रहे हैं। इसमें पहला वाद 25 सितंबर को लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने दायर किया था, जबकि दूसरा वाद हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने 15 दिसंबर को दायर किया था। तीसरा वाद 22 दिसंबर को अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में दायर किया था इन मामलों में सुनवाई के लिए अलग-अलग तारीखें निर्धारित की गई हैं।

नियोजन नीति से जुड़ीं बहालियां रद, हजारों सरकारी नौकरियों पर खतरा

रांची । राज्य कैबिनेट ने नियोजन नीति के तहत जिलास्तरीय पदों पर दस वर्ष के लिए स्थानीय लोगों को आरक्षण का प्रावधान करनेवाले संकल्प को वापस ले लिया है। हाईकोर्ट ने पहले ही इसे रद करने को कहा था। अब अधिसूचित और गैर अधसिसूचित जिलों के लिए जारी दोनों संकल्पों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रक्रियाधीन तमाम नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएंगी और नए सिरे से विज्ञापन निकालकर नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

जिन लोगों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उनकी नियुक्ति को अपूर्ण मानते हुए इससे संबंधित विज्ञपनों को निरस्त कर दिया गया है। इससे पंचायत सचिवों का मामला तो फंस ही गया है, शिक्षकों की नियुक्ति और अन्य कई जिला और राज्य स्तरीय नियुक्तियां अवरुद्ध हो गई हैं। जिनकी नियुक्ति हो गई है उनका मामला कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा और फिलहाल जो जहां हैं वहीं काम करते रहेंगे।

राज्य कैबिनेट ने बुधवार को नियोजन नीति के संकल?प वापस लेने के इस प्रस्ताव के साथ ही 45 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन प्रस्तावों में बजट सत्र के लिए तिथियों का निर्धारण भी है। 26 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा और 3 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में जनजातीय परामर्शदातृ समिति के लिए नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

बीस सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे जबकि कल्याण मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा 15 अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधायकों को सदस्य के तौर पर मनोनीत किया जाएगा और इसी बिरादरी के तीन अन्य सदस्य भी मनोनीत होंगे। सभी मनोनयन मुख्यमंत्री की अनुमति से होगा। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान नियमों को तोड़कर आनेवाले श्रमिकों पर से मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी को राज्य का निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। कैबिनेट ने धनबाद सदर अस्पताल में चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक एवं दंत चिकित्सकों के 24 पदों का सृजन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। दूसरी ओर रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के लिए 303.62 एकड़ भूखंड देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसमें 27.34 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार को दी जाएगी और 271.28 एकड़ भूखंड लीज पर दिया जाएगा।

कोरोना काल में जारी लॉकडाउन प्रावधानों के उल्लंघन के तहत दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गई है।

कुशवाहा व मुसलमान चेहरों पर जदयू ही नहीं बीजेपी की भी टिकी हैं नजरें

पटना । नीतीश सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के नाम पर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। भावी नुमाइंदों के नाम तय नहीं होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल, जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, कुशवाहा और मुसलमान चेहरों पर बीजेपी की भी नजरें टिकी हुई हैं।

कुशवाहा और मुसलमान चेहरों का प्रतिनिधित्व चाहती है बीजेपी

कैबिनेट विस्तार में हर हाल में बीजेपी सीधे तौर पर कुशवाहा और मुसलमान चेहरों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहती है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन और पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी को कैबिनेट में शामिल करने तैयारी है। वर्तमान में दोनों समाज से कैबिनेट में कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी इसी आधार पर पहली बार मुसलमान चेहरे पर दांव लगाना चाहती है।

पार्टी इसका दूरगामी परिणाम देख रही है। फिलवक्त बीजेपी में तीन

कुशवाहा विधायक हैं। इसमें पिछली सरकार में बीजेपी ने सीमांचल के प्राणापुर से विधायक विनोद सिंह को मंत्री बनाया था। विनोद दिवंगत हो गए। पूर्व मंत्री की पत्नी निशा सिंह 17वीं विधानसभा में पहली बार जीत कर आई हैं। वहीं, बिहारशरीफ से डॉ. सुनील कुमार तीसरी बार और रक्सौल के विधायक प्रमोद सिन्हा पहली बार जीते हैं।

बीजेपी की पैनी नजर जेडीयू के कुर्मी और कुशवाहा वोट बैंक पर टिकी है। खासकर आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर उमेश सिंह कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद दलों के बीच दोनों समाज को तवज्जो देने की अंदरखाने में होड़ है। कैबिनेट विस्तार में बीजेपी का सर्वाधिक जोर कुशवाहा चेहरे पर है।

पार्टी इसबार विधान पार्षद सम्राट चौधरी को मंत्री बनाना चाह रही है। दो कारणों से बीजेपी में सम्राट के नाम पर जोर है। पहला सामाजिक और दूसरा क्षेत्रीय समीकरण है। सम्राट पहले भी मंत्री रह चुके हैं।

जेडीयू के उमेश कुशवाहा के जवाब हैं बीजेपी के सम्राट चौधरी

बीजेपी के दिग्गजों के अनुसार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के जवाब के रूप में सम्राट चौधरी को उभार देना चाहती है। पार्टी सभी दृष्टिकोण से सम्राट के जरिए कुशवाहा को मुफीद मान रही है। इस बिंदु पर गत दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में जेपी नड्डा के साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल, उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद एवं रेणु देवी, बिहार के संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में लंबी बैठक चली थी। इसमें सम्राट के नेतृत्व क्षमता और अनुभव को देखते हुए सभी नेताओं को जोर था।

जो बीच बजरिया तूने...पर माइकल जैक्शन अवतार में दिखे डॉक्टर साहब, आशा भी शकीरा से कुछ कम नहीं

मुजफ्फरपुर । कोवडि-19 ने पूरी दुनिया को जो दुख दिया उससे हम सभी परिचित हैं। सबको परेशानी से दो चार होना पड़ा। इस हालत में जब महामारी से बचाव का टीका किसी के हाथ लगे तो आह्लादित होना सहज ही है। पूर्वी चंपारण स्थित सदर प्रखंड के पीएचसी में कुछ ऐसा ही हुआ। जब कोरोना की वैक्सीन यहां पहुंची तो यहां के कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब सरकार की ओर से टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ करने की घोषणा की गई तो इस पीएचसी के कर्मचारियों ने खुशी के इस मौके को सेलब्रिट करने की योजना बनाई। अस्पताल परिसर को रंग बिरंगे बैलून से सजाया गया। तालियों के बीच दीप प्रज्ज्वलति कर वधिवित रूप से इसकी शुरुआत की गई। यहां तक सभी वैसा ही हुआ, जैसा अन्य समारोहों में होता है। इस बीच समारोह के लिए मंगाए गए म्यूजिक सस्टिम पर जो बीच बजरिया तूने पकड़ी बईयां... और तू चीज बड़ी है मस्त मस्त... जैसे गाने बजने लगे। फिर क्या था पीएचसी के प्रभारी डॉ श्रवण पासवान झूमने लगे। उन्हें देख एक आशा भी बीच में आ गईं और दोनों की युगलबंदी में उपस्थति कर्मचारियों ने देर तक गीत और नृत्य का आनंद उठाया। जैसा अक्सर होता है, उपस्थति कर्मचारियों ने इस यादगार लम्हे को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लयिा। कुछ ही देर बाद डॉक्टर साहब के इस माइकल जैक्शन अवतार का वीडयिो वायरल होने लगा। लोगों ने दबी जुबान आशा के शकीरा रूप की चर्चा करने लगे।

इस इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडयिो के बारे में कहा जा रहा है कि यह 30 जनवरी को शूट कयिा गया था। इस बारे में जब पीएचसी प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की शुरुआत का वह दिन था। कर्मचारियों के मन में इसके प्रति व्याप्त भय को दूर करने की कोशशि के तहत यह कयिा गया। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

वृंदावन में साइकिल पर दिखा तेज प्रताप का भक्त अवतार, पटना में ऐश्वर्या को घुमाने व गिरने की तस्वीरें भी हो चुकीं वायरल

पटना । राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने जरा हटकर अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनका भक्ति भाव भी कुछ अलग रहा है। तेज प्रताप कभी भगवान शिव तो कभी भगवान कृष्ण का रूप धरते हैं। कभी शंख तो कभी बांसुरी बजाते हैं। उनका वृंदावन से भी पुराना लगाव रहा है।

तेज प्रताप यादव एक बार फिर वृंदावन में धूम मचाए हुए हैं। वृंदावन की सड़कों पर साइकिल चलाने का उनका मस्त अंदाज देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वैसे, शादी के बाद पत्नी ऐश्वर्या राय को साइकिल से घुमाते उनकी वायरल हुई तस्वीर भी लोग भूले नहीं हैं। एक बाद पटना में साइकिल चलाते हुए वे अपनी ही एस्कॉर्ट गाड़ी गाड़ी से रेस लगा बीच सड़क पर गिर भी चुके से रेस लगा बीच सड़क पर गिर भी चुके हैं।

वृंदावन में साइकिल पर नजर आए लालू के लाल- लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव बुधवार को वृंदावन में एक बैट्री चालित साइकिल पर घूमते नजर आए। पीली धोती, बगलबंदी और गले में शॉल ओढ़े तेज प्रताप ठेठ ब्रजवासी नजर आ रहे थे। वृंदावन में तेज प्रताप को पंचकोसी परिक्रमा करते देख वहां मौजूद श्रद्धालु वाह-वाह करते दिखे। सड़कों पर श्रद्धालु एवं आम लोग तेज प्रताप को देख रहे थे। उनके साथ सुरक्षाकर्मी और मित्र भी दूसरी साइकिलों पर थे। तेज प्रताप यादव मथुरा-वृंदावन बराबर आते रहते हैं। वृंदावन में उनकी कृष्ण भक्ति की खबरें भी आती रहीं हैं। लेकिन शायद पहली बार वे साइकिल से शहर में निकले।

बिहार की सियासत पर बोलने से किया इनकार- वृंदावन में तेज प्रताप के यूं घूमने की बात जगंल की आग की तरह फैल गई। इस बीच सूचना पर पहुंचे मीडियाकर्मियों ने जब तस्वीर लेनी शुरू की, तब उन्होंने इससे मना करते हुए मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे डाली। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे बिहार में मचे सियासी घमासान पर सवाल किए तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया।

पत्नी ऐश्वर्या संग साइकिल पर आए थे नजर -विदित हो कि तेज प्रताप यादव को साइकिल चलाने का पुराना शौक रहा है। महागठबंधन की सरकार के वक्त स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए वे कई बार पटना की सड़कों पर साइकिल चलाते देखे गए थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा पसाद राय की पोती व पूर्व मंत्री चंदिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से शादी के बाद पत्नी को साइकिल पर घुमाते हुए एक उनकी तस्वीर भी वायरल हो गई थी। यह तस्वीर 12 मई 2018 को तेज प्रताप एवं एश्वर्या की शादी के कुछ ही दिनों बाद सामने आई थी। इसमें दोनों एक-दूसरे की आंखों में आखें डाले साइकिल की सैर करते देखे गए थे। हालांकि, अब तेज प्रताप ने ऐश्वर्या के खिलाफ तलाक का मुकदमा कर रखा है।

सड़क पर साइकिल से गिर चुके लालू के लाल- एक बार साइकिल सवार तेज प्रताप यादव पटना की सड़क पर अपनी एस्कॉर्ट पार्टी की गाड़ी से रेस लगा बैठे थे। इस दौरान संतुलन बिगड़ने के कारण वे सड़क पर ही गिर पड़े। उन्हें हल्क चोटें आई थीं। तेज प्रताप की वह तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। दरअसल, तेज प्रताप यादव 26 जुलाई 2018 को आरजेडी की साइकिल रैली का निमंत्रण देने साइकिल से निकले थे और साइकिल दुर्घटना के शिकार हो गए थे।

तेज प्रताप यादव के रहे हैं और भी कई अंदाज- इसके अलावा तेज प्रताप बाइक चलाते व घुड़सवारी करते भी देखे जाते रहे हैं। तेज प्रताप के और भी कई अंदाज रहे हैं। वे कभी हवलाई या राज मिस्त्री बने तो कभी ट्रैक्टर या रिक्शा पर चढ़े भी नजर आ चुके हैं। तेज प्रताप को अभिनय का भी शौक है। वे फिल्मों में भी काम कर चुके हैं।

कोडरमा के डोमचांच में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दंपत्ति की मौत

डोमचांच (कोडरमा)। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के महेशपुर पुल के समीप एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दंपत्ति की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना में दोनों का सिर बुरी तरह कुचल गया। मिली जानकारी के अनुसार डोमचांच के दो दुरोडीह निवासी विनोद यादव (45) व किरण देवी (35) बाइक संख्या जेएच 9बी 3659 पर सवार होकर डोमचांच से डुमरी (गिरिडीह) जा रहे थे। डुमरी में मृतका किरण देवी का मायका है। विनोद यादव अपनी पत्नी किरण देवी को मायके छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात 12 चक्का वाहन ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में दोनों का सर बुरी तरह कुचल गया है। पुलिस दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ट्रक की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

एक नजर

हाईकोर्ट में जजों के 419 और सुप्रीम कोर्ट में 4 पद खाली, लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी

नई दिल्ली । कानून मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि 25 हाईकोर्टों मे 419 और सुप्रीम कोर्ट में जजों की चार रिक्तियां है। सरकार ने कहा है कि ये रिक्तियां कितने समय में भर दी जाएंगी, कहा नहीं जा सकता। जजों की सबसे ज्यादा रिक्तियां दिल्ली, कोलकाता और बंबई हाईकोर्ट में क्रमशः 31, 40 और 30 रिक्तियां हैं। सरकार ने बताया की पिछले तीन वर्षों (2018,19 और 20) में हाई कोर्ट कोलेजियम से 505 सिफारिशें प्राप्त हुई थीं, सुप्रीम कोर्ट की सिफरिश पर इनमें से 177 सिफारिशें को विभिन्न हाईकोर्ट में नियुक्ति दी गई। वहीं 134 नामों को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने खारिज कर दिया और हाईकोर्ट को वापस भेज दिया। सरकार उन्ही सिफारिशें को नियुक्ति के लिए मंजूर करती हैंजो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से क्लियर हो जाती हैं। सरकार के पास विभिन्न हाईकोर्ट से प्राप्त 194 सिफारिशें हैं जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियागत है। सरकार ने कहा की जजों की रिक्तियां भरना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार और न्याय पालिका के सहयोग से जजों की नियुक्तियां की जाती हैं। इसके लिए विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारों से विभिन्न स्तरों पर परामर्श भी किया जाता है। इसलिए उच्च न्यायपालिका मे जजों की रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

हैरान करने वाला दावा- भारत में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं 30 करोड़ लोग

नई दिल्ली । देश में किए गए एक सरकारी सीरोलॉजिकल सर्वे से जुड़े अधिकारी ने बताया कि भारत में वास्तविक कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक है। पिछले सप्ताह सामने आए सीरोलॉजिकल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 30 करोड़ यानी लगभग हर चौथा व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका है।

देश की कुल आबादी का एक चौथाई हिस्सा यानी 30 करोड़ लोगों में कोरोना एंटीबॉडी मिली है। यह सर्वे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से किया गया है। परिषद का कहना है कि उन्होंने अभी सर्वे के दौरान सामने आए रिजल्ट की जानकारी दी है। सर्वे में कितने लोगों को शामिल किया गया, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है। विश्व स्वास्थ्य का कहना है कि संक्रमण की प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 60 से 70 प्रतिशत आबादी में एंटीबॉडी होना आवश्यक है।

अगस्त-सितंबर में भी किया था एक अन्य सर्वे-इसके अलावा अगस्त और सितंबर में भी एक सर्वे किया गया था। इसमें 29 हजार लोगों को शामिल किया गया था। ये सभी 10 साल से ज्यादा की उम्र के थे। सभी के ब्लड सैंपल की जांच की गई थी। उस समय 15 में से एक व्यक्ति में कोरोना की एंटीबॉडी मिली थी। वहीं, शहर के स्लम एरिया के 6 में से एक व्यक्ति में कोरोना की एंटीबॉडी मिली थी। दिल्ली सरकार की ओर से जारी सीरो सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया था कि दो करोड़ की आबादी वाले शहर में 56 प्रतिशत आबादी यानी हर दूसरा व्यक्ति कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है।

कलह से बचने को असम में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी कांग्रेस

नई दिल्ली । असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। चुनाव के बाद महागठबंधन सत्ता तक पहुंचता है तो सभी दलों के साथ चर्चा के बाद तय किया जाएगा। पर पार्टी की चुनाव रणनीति लोकसभा सांसद गौरव गोगोई के इर्दगिर्द रहेगी, ताकि भविष्य में उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के निधन के बाद कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है। नए नेता के नाम पर पार्टी के अंतर गंभीर मतभेद हैं। इसलिए, पार्टी चुनाव में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मौजूदा स्थिति में पार्टी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है, तो बिना चेहरे के लड़ना होगा।

असम से जुड़े एआईसीसी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि असम में गौरव गोगोई के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। गौरव गोगोई की अकेले ऐसे नेता है, जो असम के सभी भागों में असर रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता तरुण गोगोई के निधन के बाद गौरव गोगोई ने प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर सभाएं भी की हैं। पार्टी नेता ने कहा कि चुनाव से पहले गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से असम कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बढ जाएगी। इससे पार्टी को चुनाव में नुकसान होगा। इसलिए, पार्टी उन्हें उम्मीदवार घोषित करने से परहेज करेगी, पर चुनाव प्रचार में उन्हें अहमियत देकर लोगों को संकेत जरुर देगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि भाजपा के तमाम दावों के बावजूद महागठबंधन सत्ता की दहलीज तक पहुंच सकता है। इसके लिए वह दूसरे छोटे दलों को भी गठबंधन में शामिल करने की तैयारी कर रहा है, ताकि भाजपा और गठबंधन में सीधा मुकाबला हो। पार्टी नेता ने कहा कि मुकाबला त्रिकोणीय होता है, तो इसका फायदा भाजपा को मिलेगा।

रिहाना को लता मंगेशकर ने भी दिया जवाब, कहा- हम खुद सुलझा सकते हैं अपनी समस्याएं

नई दिल्ली । किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट कर घिरीं रिहाना समेत विदेशी हस्तियों को एक के बाद एक भारत के प्रमुख लोग जवाब दे रहे हैं। बॉलीवुड से जुड़े तमाम सेलिब्रिटीज के ट्वीट करने के बाद अब भारत रत्न लता मंगेशकर ने रिहाना-ग्रेटा थनबर्ग को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझा सकते हैं।

लता मंगेशकर ने ट्वीट कर लिखा है, भारत गौरवशाली राष्ट्र है और हम सभी भारतीय सिर ऊंचा करके खड़े हैं। एक गर्व करने वाले भारतीय के रूप में, मुझे पूरा विश्वास है कि जिन मुद्दों या समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, हम उनके लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, उनका समाधान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। इसके साथ ही उन्होंने भी अपने ट्वीट में इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगैंडा हैशटैग का इस्तेमाल किया।

बता दें कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम करने वालीं ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अनेक लोगों ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया था। पॉप स्टार रिहाना ने एक खबर साझा की थी जिसमें कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद करके किसानों के खिलाफ केंद्र की कार्रवाई का जिक्र किया गया था, इसके बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ निहित स्वार्थी समूह प्रदर्शनों पर अपना एजेंडा थोपने का प्रयास कर रहे हैं और संसद में पूरी चर्चा के बाद पारित कृषि सुधारों के बारे में देश के कुछ हिस्सों में किसानों के बहुत ही छोटे वर्ग को कुछ आपत्तियां हैं।

थनबर्ग ने मंगलवार को ट्वीट किया कि हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं। उन्होंने इसके साथ ही सीएनएन की एक खबर टैग की जिसका शीर्षक था प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस में झड़प के बीच भारत ने नई दिल्ली के आसपास इंटरनेट सेवा बंद की। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रदर्शन के बारे में जल्दबाजी में टिप्पणी से पहले तथ्यों की जांच-परख की जानी चाहिए और सोशल मीडिया पर हैशटैग तथा सनसनीखेज टिप्पणियों की ललक न तो सही है और न ही जिम्मेदाराना है।

गणतंत्र दिवस की घटना के लिए किसान जिम्मेदार नहीं, शांति से निपटे सरकार- पूर्व पीएम देवगौड़ा

नई दिल्ली । संसद का बजट सत्र जारी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को लेकर बुधवार को दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। इसे लेकर आज भी हंगामे के आसार हैं। इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कहा कि हम गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुए उपद्रव की निंदा करते हैं, लेकिन किसान इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। विरोध स्थल पर कंक्रीट की दीवारें लगाने के केंद्र के फैसले से कुछ हासिल नहीं होगा। सरकार को मामले में शांति से निपटना चाहिए। गणतंत्र दिवस की घटना के लिए किसान जिम्मेदार नहीं हैं, हैं। राज्य सरकार की राय भी लेनी चाहिए।

बता दें कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दो पालियों में आयोजित हो रही हैं। बैठकें पांच-पांच घंटे की पारी में आयोजित हो रही हैं। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह होती है और दोपहर के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है।

राज्यसभा में दिखी ऐसी जुगलबंदी, दिग्विजय बोले- वाह जी महाराज तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा- आपका ही आशीर्वाद

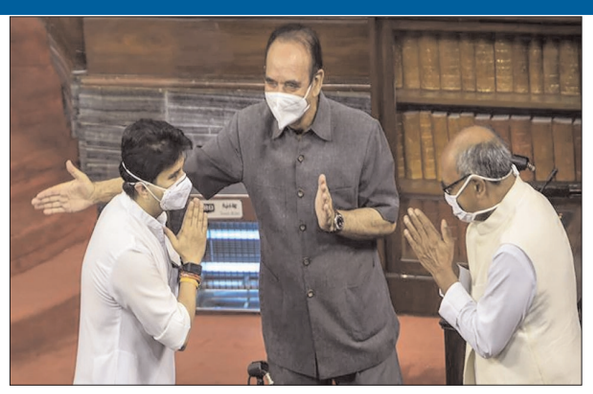

नई दिल्ली । राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आज कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह एक-दूसरे से अलग ही अंदाज में बातें करते दिखे. बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि सुधार के मसले को लेकर कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया. ज्योतिरादित्य सिंधिया के ठीक बाद भाषण देने उठे कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया जी को बधाई. मैं आपको बधाई देता हूं, जितने अच्छे ढंग से आप यूपीए के कार्यकाल के दौरान यूपीए का पक्ष सदन में रखते थे, आज आपने बीजेपी का पक्ष सदन में रखा है, वाह जी महाराज वाह. इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यह सब आपका आशीर्वाद है. इस पर दिग्विजय बोले- हमारा आशीर्वाद आपके साथ था और आगे भी रहेगा.

बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में कृषि सुधार का एजेंडा पेश किया गया था. उस समय के हमारे कृषि मंत्री शरद पवार ने 2010-2011 में हर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि कृषि में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी जरूरी है और इसके लिए एपीएमसी कानून में संशोधन होना चाहिए. जुबान बदलने की आदत हमें बदलनी होगी. पट भी मेरा और चट भी मेरा .. यह कब तक चलेगा?

इससे पूर्व राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राजद सांसद मनोज झा ने आज राज्य सभा में नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली सीमा पर की गई भारी बैरिकेडिंग, कंटीले तारों से घेराबंदी पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने सदन से पूछा कि अगर जेपी इस तरह की कंटीली तारों को देखते तो क्या सोचते?

राजद सांसद ने कहा, महोदय, मैं कभी देश की सरहद पर नहीं गया लेकिन ऐसी तस्वीरें वहां की भी कभी नहीं देखी हैं. दिल्ली की सीमाओं पर सरिए, कीलें लगाई गई हैं और खाई बनाई जा रही है... ऐसी तस्वीरें हमने सरहद पर पर भी नहीं देखी है. अगर आज जेपी होते तो इसे देखकर क्या सोचते? झा ने कहा, सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर.. पूरे देश में चर्निंग हो रही है.

उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप किससे लड़ रहे हैं? आप किसानों से लड़ रहे हैं. आपसे चांद नहीं मांग रहे हैं, वो अपना हक और हुकूक मांग रहे हैं. उन्होंने कहा, ÷आपमें या हम लोगों में से चाहे व सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, यह मुगालता ना रहे कि वह किसानों का हित उनसे बेहतर समझते हैं.÷

झा ने कहा, किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन मोनोलॉग और डायलॉग में फर्क होता है. आप मोनोलॉग को डायलॉग में बदल दे रहे हैं. उन्होंने कहा, ÷बिहार में एमएसपी 2006 में खत्म की गई. आज बिहार के किसान खेतिहर मजदूर बन कर रह गए हैं. क्या आप बिहार मॉडल को पूरे देश में लाना चाहते हैं?

केरल नें खुलने जा रहा है राज्य का पहला मानव दूध बैंक, ऐसे आएगा शिशुओं के काम

नई दिल्ली । केरल में शुक्रवार को पहला मानव दूध बैंक खुलने जा रहा है। इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा द्वारा कोच्चि के सरकारी स्वामित्व वाले एर्नाकुलम सामान्य अस्पताल में किया जाएगा। बता दें कि यह सुविधा उन नवजात शिशुओं को स्तन का दूध उपलब्ध कराएगी, जो बीमारी या किन्हीं और कारणों से अपनी माताओं के दूध से वंचित हैं।

राज्य सरकार के अनुसार, सामान्य अस्पताल में एक वर्ष में 3,600 बच्चे जन्म लेते हैं और उनमें से 600 से लेकर 1,000 बीमार शिशुओं को नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में भर्ती कराया जाता है। रोटरी कोचीन ग्लोबल के डॉ पॉल पी जी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, ÷बैंक से स्तन का दूध संक्रमणों के जोखिम को कम करेगा और नवजात शिशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा।

अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि जरूरतमंद बच्चों को स्तन के दूध को इकट्ठा करने, संरक्षित करने और प्रदान करने के लिए सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाएं सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दूध को 6 महीने तक सुरक्षित रूप से बैंक में संग्रहित किया जा सकता है।

शुरुआत में, दूध केवल अस्पताल के एनआईसीयू में भर्ती शिशुओं को ही मुफ्त में दिया जाएगा। बाद में, कई संग्रह और सुरक्षित वितरण बिंदुओं के लिए अस्पतालों के एक नेटवर्क की योजना बनाई जाएगी।इस बैंक में दान करने वाले अस्पताल की माताएँ होंगी जिन्होंने बच्चों को वहाँ पहुँचाया होगा। इस मानव दूध बैंक को रोटरी क्लब ऑफ कोचीन ग्लोबल की साझेदारी में स्थापित किया जा रहा है। यह पूरे देश में खुलने वाला 15 वां दूध बैंक है।

आरोपी के पास से सिर्फ नोट बरामदगी पर्याप्त साक्ष्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि भ्रष्टाचार रोधी कानून के प्रावधानों के तहत महज नोट की बरामदगी के आधार पर अपराध साबित करने और आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आरोप नहीं बनता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए बिना किसी संदेह के आरोप साबित करना होगा कि आरोपी ने अपनी इच्छा से रिश्वत की रकम स्वीकार की। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि यह तय व्यवस्था है कि महज बरामदगी से आरोपी के खिलाफ अभियोजन का आरोप साबित नहीं होता। भ्रष्टाचार रोधी कानून, 1988 की धारा सात, 13 (एक) (डी) (आई) और (आईआई) के तहत कहा गया है कि बिना किसी संदेह के आरोप साबित होना जरूरी है कि आरोपी को पता था कि जो रकम उसने स्वीकार की, वह रिश्वत है। शीर्ष अदालत ने कहा कि घूस मांगे जाने का कोई सबूत नहीं होने और महज नोट की बरामदगी से अपराध साबित नहीं हो जाता। मदुरै नगर निगम में सफाई निरीक्षक रहे एन विजयकुमार की अपील पर यह फैसला आया। उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया था। निचली अदालत ने मामले में उन्हें बरी कर दिया था लेकिन इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा तिरुवनंतपुरम जिले के कोवियार में नव निर्वाचित पार्षदों और ब्लॉक, जिला पंचायत सदस्यों को संबोधित करते हुए।

अभी नहीं टला कोरोना का खतरा, बीते 24 घंटों में सामने आए 12 हजार से ज्यादा मामले

नई दिल्ली । भारत में कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश टीकाकरण शुरू होने से राहत महसूस कर रहा है। लेकिन, वायरस का खतरा अभी तक टला नहीं है। पिछले 24 घंटों में देशभर में कोरोना के 12,899 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना के कुल आंकड़े 1,07,90,183 तक पहुंच गए हैं।

वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 107 लोगों की मौत हो गई है जिससे देश मो कोरोना का डेथ टॉल 1,54,703 पहुंच गया है। एक ओर जहां 1,04,80,455 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं वहीं 1,55,025 लोग अब भी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। बीते 24 घंटों मे 17,824 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। भारत कोरोना के खिलाफ डट कर लड़ाई लड़ रहा है, पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया है और दूसरे चरण में फंट लाइन् वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिए आंकड़ो के मुताबिक अब तक देशभर् में 44,49,552 लोगों को टीका लगाया जा चुका है।

रिहाना-ग्रेटा के बवाल के बाद अब ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन पर चर्चा कराने पर विचार

नई दिल्ली । किसान आंदोलन के समर्थन में सिंगर रिहाना और पर्यावरण के लिए काम करने वालीं ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट्स के बाद इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और तूल देकर भारत सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है। ब्रिटेन की संसद की याचिका समिति किसानों के प्रदर्शन और भारत में प्रेस की आजादी पर हाउस ऑफ कॉमन्स परिसर में चर्चा कराने पर विचार कर रही है। दरअसल, इस सबंध में एक ऑनलाइन याचिका पर 1,06,000 से ज्यादा हस्ताक्षर किए गए हैं। यह चर्चा वेस्टमिंस्टर हॉल में हो सकती है।

क्या हैं चर्चा कराने के नियम?

ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करने वालों की सूची में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का नाम भी कथित तौर पर दिख रहा है, जो उन्होंने पश्चिम लंदन से संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य की हैसियत से किए हैं। वहीं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास सह कार्यालय, 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने बुधवार को इस बात से इनकार किया कि जॉनसन ने याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। यहां जानना जरूरी है कि संसद की वेबसाइट पर अगर किसी ई-याचिका पर 10,000 से ज्यादा हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं, तो ब्रिटेन की सरकार के लिए आधिकारिक बयान देना जरूरी हो जाता है, जबकि किसी याचिका पर एक लाख से ज्यादा हस्ताक्षर होते हैं तो उस मुद्दे पर चर्चा के लिए विचार किया जाता है।

भारत को घेरने की तैयारी

ब्रिटिश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और दुनियाभर के पत्रकारों को अपनी नौकरी करने और गिरफ्तारी या हिंसा के डर के बिना अधिकारियों को जवाबदेह रखने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा, स्वतंत्र प्रेस हमारे लोकतंत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सरकार मीडिया स्वतंत्रता गठबंधन के सदस्य के जरिए इसे अपना समर्थन देती है। संसद की आधिकारिक याचिका वेबसाइट पर प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा और प्रेस स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से आग्रह करें शीर्षक की याचिका में ब्रिटिश सरकार से किसान प्रदर्शन और प्रेस की आजादी पर सार्वजनिक बयान देने क अनुरोध किया गया है।

इस महीने के अंत तक चर्चा

हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रवक्ता ने कहा कि याचिका पर सरकार की प्रतिक्रिया इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद है और चर्चा कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि वेस्टमिंस्टर हॉल में चर्चा कराने पर फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक है। यहीं पर याचिकाओं पर चर्चा होती है। लेकिन समिति इस चर्चा को जल्द से जल्द कराने की घोषणा कर सकती है। इस बीच, ब्रिटेन में इंडिन जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (आईजेए) ने अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों के साथ मिलकर किसान आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकारों की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है और भारत सरकार से देश में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

वहीं, दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि प्रदर्शन के बारे में जल्दबाजी में टिप्पणी से पहले तथ्यों की जांच-परख की जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय ने कहा है कि कुछ निहित स्वार्थी समूह प्रदर्शनों पर अपना एजेंडा थोपने का प्रयास कर रहे हैं और संसद में पूरी चर्चा के बाद पारित कृषि सुधारों के बारे में देश के कुछ हिस्सों में किसानों के बहुत ही छोटे वर्ग को कुछ आपत्तियां हैं। विदेश मंत्रालय के बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रदर्शनों को भारत के लोकतांत्रिक चरित्र और राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

भारत सरकार ने विदेशी प्रोपेगेंडा को खारिज किया- दरअसल, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के जरिए चलाए जा रहे विदेशी प्रोपेगेंडा का भारत ने बुधवार को करारा जवाब दिया था। भारत के अंदरुनी मामले किसान आंदोलन पर दखलअंदाजी करने वालीं पॉप गायिका रिहाना, एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग सहित मशहूर विदेशी हस्तियों के दुष्प्रचार पर विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि ये भारत का आंतरिक मामला है और विदेशी शख्सियतों को गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करने से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भी कहा था कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को तोड़ नहीं सकता है। ना ही कोई भारत तो नई ऊंचाई पाने से रोक सकता है।

इन लोगों ने की दखलअंदाजी

अमेरिकी पॉप गायिका रिहाना, स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकी अभिनेत्री अमांडा केरनी, अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस सहित कई मशहूर हस्तियों ने भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में ट्वीट किए । इसको लेकर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। विदेश मंत्रालय के अलावा सरकार के कई मंत्रियों और खेल से बॉलिवुड तक की हस्तियों ने करारा जवाब दिया।

जेल से रिहा होने से एक दिन पहले दूध व्यापारी की जेल में मौत

सूरत । गुजरात के सूरत शहर की लाजपोर जेल में उस जेल प्रशासन के उस वक़्त हाँथ-पैर फूल गए जब सजा काट रहे एक कैदी की अचानक तबियत बिगड़ गई और उसने सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि, जेल प्रशासन ने बीमार होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। वही, परिजनों ने जेल में हुई कैदी से मारपीट के कारण मौत होने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि कैदी 3 फरवरी को जेल से रिहा होने वाला था, रिहाई से एक दिन पहले ही उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, कच्छ-भुज में मारपीट और हमले का 32 वर्षीय आरोपी असलम इस्माइल चाकी पासा के तहत लाजपोर जेल में सजा काट रहा था। लाजपोर जेल में तीन महीने से सजा काट रहे कैदी की मंगलवार को अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। असलम की मौत की जानकारी मिलते ही पूरा परिवार सूरत आ गया। परिवार ने बताया कि, शनिवार को असलम ने भाई से फोन पर बातचीत के दौरान बताया था कि जेल में उसकी ड्रग्स के एक आरोपी से बात पर मारपीट हुई थी। घटना के बाद उसके हाथ और पैर में तेज दर्द होने लगा था। साथ ही परिवार ने फॉरेंसिक पोस्टमार्टम करवाने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि, असलम की मौत बीमारी से नहीं बल्कि पिटाई से हुई है। वहीं, पुलिस अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में मौत का कारण बीमारी बता रही है।

डॉक्टरों ने बताया कि, पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि मृतक के पेट में खाने की थैली पलटकर सीने में आ गई थी। इस वजह से उसकी मौत हुई। हालांकि हिस्टोपैथी आदि सैंपल लेकर लैब में भेज दिए गए हैं। फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। हालांकि, प्राथमिक रिपोर्ट से परिवार के आरोप की पुष्टि हो रही है। फॉरेंसिक पीएम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि चोट लगने के कारण ही मौत हो सकती है। वहीं, पीएम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण सामने आएगा।

प्रकरण पर जानकारी देते हुए जेल सुपरिंटेंडेंट मनोज निनामा ने बताया कि, कैदी को सांस की बीमारी थी, इसलिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक को टीबी की शिकायत थी। कैदी की जेल में किसी से मारपीट नहीं हुई न ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी।

शशि थरूर को नहीं भाया रिहाना को सचिन-विराट का जवाब, बोले- क्रिकेटर के ट्वीट से नहीं हो सकती भरपाई

नई दिल्ली । किसान आंदोलन को लेकर रिहाना जैसी कुछ विदेशी हस्तियों ने जैसे ही प्रतिक्रिया दी कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, लता मंगेशकर जैसी हस्तियों ने एकजुटता दिखाते करारा जवाब दिया है। उन्होंने यह संदेश देने कि कोशिश की है कि यह हमारा आंतरिक मामला है। हम इसे सुलझा लेंगे। हालांकि कांग्रेस नेता शशि थरूर को यह नहीं भाया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के लिए यह शर्मनाक है।

शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा, भारतीय हस्तियों को विदेशी हस्तियों के बयान पर प्रतिक्रिया देना शर्मनाक है। भारत की वैश्विक छवि को भारत सरकार की उदासीनता और अलोकतांत्रिक व्यवहार से होने वाले नुकसान की भरपाई क्रिकेटर के ट्वीट से नहीं हो सकती।% साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले और किसानों के साथ चर्चा करे। थरूर ने कहा कि इसका हल तभी निकलेगा। सचिन बोले- यह हमारा आंतरिक माला

किसान आंदोलन को लेकर कुछ दिग्गज विदेशी हस्तियों के ट्वीट्स के बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर के जरिए उन्हें जवाब दिया है। सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा, भारत की संप्रभुता से किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें देख सकती हैं, लेकिन इसमें हिस्सा नहीं ले सकती हैं। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत को लेकर फैसले ले सकते हैं। एक देश के तौर पर हम एक रहते हैं।

क्या बोले कोहली- विराट ने ट्वीट में लिखा, इस मतभेद के समय में हम सब साथ जुड़े रहें। किसान हमारे देश का अभिन्न हिस्सा हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मुद्दे पर दोनों दलों की सहमति से कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा, जिससे शांति आएगी और हम एकसाथ आगे बढ़ेंगे।

मशहूर पॉप स्टार रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन को लेकर भारत सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा, जिसके बाद से तमाम भारत की तमाम दिग्गज हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जवाब दिए हैं। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट प्रज्ञान ओझा के बाद सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सुरेश रैना जैसे क्रिकेटरों ने बिना नाम लिए इन विदेशी हस्तियों को जवाब दिया है। रिहाना और ग्रेटा के ट्वीट के बाद से ट्विटर पर#IndiaAgainstPropaganda #IndiaTogether ट्रेंड हो रहे हैं।

केंद्र सरकार ने भी दिया करारा जवाब- ऐसे लोगों को विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है और साफ कहा है कि सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और कमेंट्स से लुभाने का तरीका न तो सही है और नहीं यह जिम्मेदाराना है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, भारत की संसद ने पूरी चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कानून पास किए थे। ये कानून किसानों को बड़ा बाजार मुहैया कराएंगे और उनके लिए अपनी फसल बेचना पहले से आसान होगा। ये कानून पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से स्थायी खेती का रास्ता भी साफ करते हैं। भारत के किसानों के एक छोटे से हिस्से के मन में कानूनों को लेकर कुछ संशय हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने उनके प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की वार्ताएं की। केंद्रीय मंत्री बातचीत में शामिल हुए और 11 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। सरकार ने यहां तक कि कानूनों को रोकने का भी प्रस्ताव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रस्ताव दोहराया भी।

श्रुति हासन

ने प्रभास को बताया जिंदादिल इंसान, 'सालार' में साथ नजर आने वाली है ये जोड़ी

श्रुति हासन का कुछ दिन पहले ही बर्थडे था, जिसके सेलिब्रेशन की फोटोज फैंस के बीच खूब वायरल हुई थीं. श्रुति ने महामारी को ध्यान में रखते हुए अपना बर्थडे कुछ ही दोस्तों के साथ मनाया था. जब उनसे उनके बर्थडे रेसोल्यूशन के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा, बर्थडे पर मेरा कोई रेसोल्यूशन नहीं है. मैं सिर्फ खुद को बेहतर बनाने और अपने साथ ईमानदार रहने की कोशिश करती हूं. श्रुति तब भी सुर्खियों में आई थीं, जब उन्हें एक अनजान व्यक्ति के साथ देखा गया था. ऐसी अफवाहें थीं कि वह व्यक्ति कोई और नहीं शांतनु हजारिका हैं. रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे रिलेशनशिप में हैं.

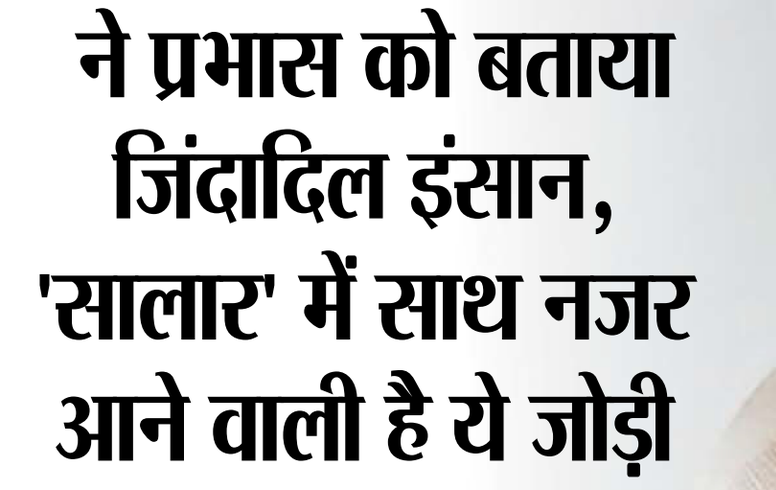

ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जब श्रुति से उनके रिलेशनशिप को लेकर पूछा गया, तब उन्होंने कहा, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानती हूं कि लोगों के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग करके देख पाना आसान होता है. इसलिए मेरा ध्यान सिर्फ काम पर है और मैं चाहूंगी कि दूसरे भी इसी पर ध्यान दें.

एक्ट्रेस ने हाल में एक्शन थ्रिलर सालार की शूटिंग शूरू की है. अपनी व्यस्तता के बारे में श्रुति ने कहा, 2021 में मैं काफी बिजी रहने वाली हूं. मेरी कड़ी मेहनत के साथ क्रिएटिव बने रहने की योजना है. सालार में अपने रोल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन यह मेरे पुराने रोल की तुलना में काफी अनूठा है और मैं अपने रोल को निभाने के लिए रोमांचित हूं. इस फिल्म के लिए प्रभास और श्रुति साथ आए हैं. प्रभास के साथ काम करने को लेकर श्रुति ने कहा, मैं प्रभास के साथ काम करने का मौका पाकर वाकई में खुश हूं. मैंने उनके साथ पहले किसी फिल्म में काम नहीं किया था. वह काफी जिंदादिल और काम को लेकर बहुत समर्पित इंसान हैं...

VIRAL VIDEO: मोनालिसा ने लगाए चुनरी-चुनरी गाने पर ठुमके, तो फैंस को याद आई बीवी नंबर 1

भोजपुरी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) ने टीवी इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया. स्टार प्लस के शो डायन से मोनालिसा (Monalisa) को घर-घर में पहचान मिली. सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली एक्ट्रेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम रील्स (Instagram Reels) पर नया वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में मोनालिसा अपनी को-स्टार श्रुति शर्मा के साथ मिलकर चुनरी-चुनरी गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं. बता दें कि मोना इन दिनों टीवी सीरियल नमक इस्क का में ग्रे शेड प्ले कर रही हैं.

वीडियो में मोनालिसा क्रीम कलर की साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही हैं. वीडियो में मोनालिसा का डांस और उनका अंदाज फैन्स को काफी पसंद आ रहा है. मोनालिसा एक्टर सलमान खान की फैन हैं और अक्सर ही वो उनकी फिल्मों के गानों पर वीडियो बनाती रहती हैं. सलमान खान की फिल्म बीवी नंबर 1 1999 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सलमान के साथ करिश्मा कपूर और सुष्मिता सेन ने काम किया था. फिल्म साल की हिट बॉक्स ऑफिस साबित हुई थी.

बता दें कि मोनालिसा टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट आई थीं. 38 वर्षीय मोनालिसा का असली नाम अंतरा बिस्वास है. मोनालिसा भोजपुरी ही नहीं सरकार राज, मनी है तो हनी है, गंगा पुत्र और काफिला जैसी बॉलीवुड फिल्में भी कर चुकी हैं. मोनालिसा ने बिग बॉस 10 में अपने बॉयफ्रेंड विक्रांत सिंह राजपूत से शादी की थी. भोजपुरी फिल्म इंड्स्ट्री में मोनालिसा को ब्यूटी विद् ब्रेन और क्वीन का खिताब मिला है. सोशल मीडिया पर भी उनका जबरदस्त क्रेज देखा जाता है. उनके इंस्टाग्राम पर चार मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं.

Bigg Boss 14: देवोलीना ने दिखाई मिडिल फिंगर तो भड़क उठीं अर्शी, दी थप्पड़ मारने की धमकी

टीवी शो बिग बॉस 14 के घर में बीती रात देवोलीना भट्टाचार्जी और अर्शी खान के बीच भयंकर लड़ाई हुई. दरअसल, राहुल वैद्य अर्शी खानको परेशान करने की प्लानिंग कर रहे थे. वह इसमें सफल भी रहे. राहुल और अली गोनी ने प्लानिंग बनाकर अर्शी खान के सामने आए और कहा कि राखी सावंत तो टॉप 3 में जाकर रहेंगी. ये बात अर्शी खान को पसंद नहीं आई और उन्होंने राखी सावंत को भड़काने के लिए इसके उलट बात कही.

अर्शी खान राखी सावंत से कहती नजर आईं, 'अली और राहुल का कहना है कि तुम इस हफ्ते घर से बेघर हो जाओगी.' जब देवोलीना भट्टाचार्जी ने इस बात की पड़ताल अली-राहुल से की तो मामला बिलकुल साफ हो गया. फिर क्या था देवोलीना अर्शी खान की बुराई करने लगी. उन्होंने अर्शी खान पर घरवालों के बीच मतभेद पैदा करने का आरोप लगाया.

इसके बाद देवोलीना और अर्शी खान के बीच खूब लड़ाई हुई. देवोलीना अपने आपे से बाहर हो गईं और अर्शी खान के साथ गाली-गलौज की और उन्हें सभी के सामने मिडिल फिंगर भी दिखा दी.

हालांकि, यहां गाली सुनने के बाद भी अर्शी खान कुछ शांत बनी रहीं और देवोलीना को दायरे में रहने की हिदायत दी. अर्शी खान यह कहती हुई नजर आईं कि अगर वो बार-बार बदतमीजी करेंगी तो वो उन्हें झापड़ मार देंगी. अब देखने वाली बात यह है कि इस लड़ाई पर सलमान खान का क्या रिएक्शन आता है.

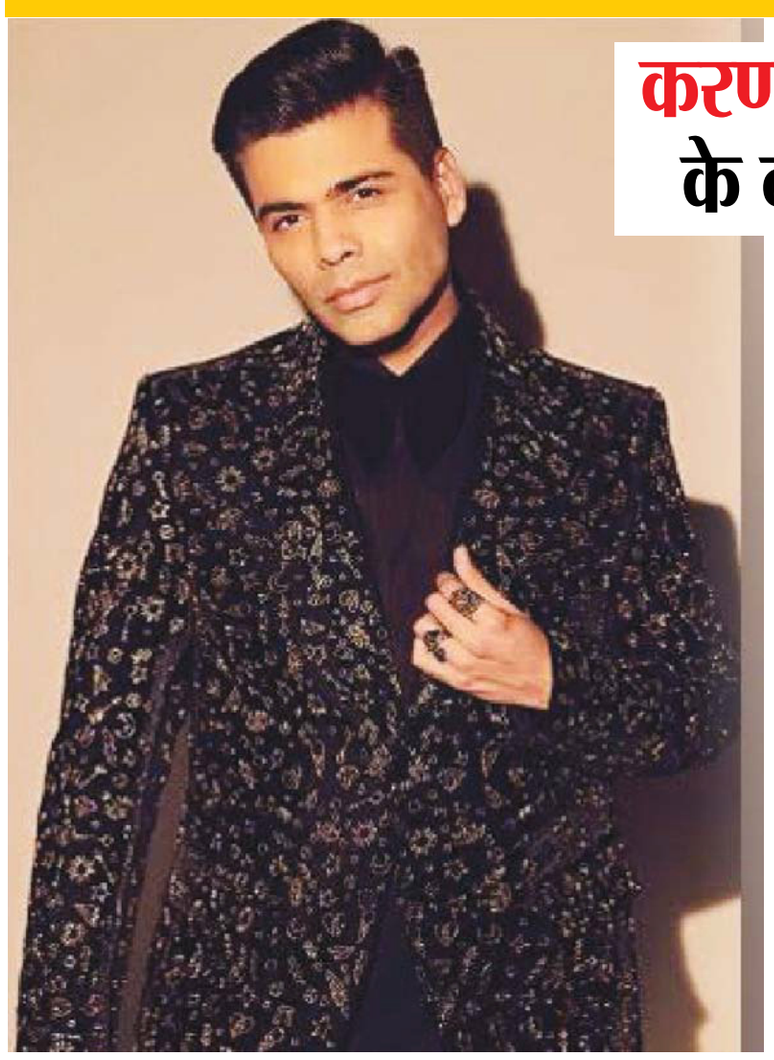

करण जौहर के मल्टीस्टारर प्रोजेक्ट 'तख्त' के बंद होने की खबर से फैंस हुए निराश

करण जौहर ने साल 2019 में अपने एक बड़े प्रोजेक्ट तख्त की घोषणा की थी. करण इस फिल्म को लेकर खासा उत्साहित थे और फिल्म में कई बड़े स्टार्स को एक साथ स्क्रीन पर लाना चाहते थे. इनमें रणवीर सिंह, करीना कपूर, आलिया भट्ट , भूमि पेडनेकर, विकी कौशल, जाह्नवी कपूर और अनिल कपूर जैसे ए लिस्टर स्टार्स की चर्चा थी.

इतने सारे चहेते स्टार्स को एकसाथ देखने को लेकर फैंस भी काफी उत्सुक थे और सोशल मीडिया पर मूवी के बारे में पूछते रहते थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म को लेकर जो न्यूज आ रही है वो फैंस को निराश कर रही है. बताया जा रहा है कि करण जौहर का ये बड़ा प्रोजेक्ट तख्त हमेशा के लिए बंद हो गया है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

कोरोना के चलते पहले इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखना पड़ा था, लेकिन अब खबर आ रही है कि ये हमेशा के लिए बंद हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट क्रिएटिव डिफरेंस के चलते बंद किया गया है. ये प्रोजेक्ट करण जौहर के सबसे महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक था जिसके लिए वह काफी जोर शोर से तैयारी कर रहे थे. यहां तक कि वो इसके लिए कई जगहों को भी देख आए थे.

साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'कलंक' भी करण का मल्टीस्टारर प्रोजेक्ट था, जो जबरदस्त फ्लॉप हो गया. इस फिल्म में भी बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स कास्ट किए गए थे, फिल्म में माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर, वरुण धवन, आलिया भट्ट जैसे स्टार्स होने के बाद भी ये फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई. खबरें तो ये भी है कि करण जौहर का इंटरेस्ट अब साउथ की फिल्मों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब साउथ की फिल्मों के लिए वह अपने बड़े प्रोजेक्ट बंद कर रहे हैं ताकी कलंक जैसी फिल्मों को करने से बचा जा सके.

हाल ही में करण ने वरुण और नताशा की शादी के बाद काफी इमोशनल होकर पोस्ट किया था. करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर वरुण धवन और नताशा दलाल की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा था कि %मैं इस पोस्ट को लिखते समय भावनाओं और यादों की भीड़ में खोया हुआ हूं. मुझे अभी भी याद है जब मैं इस बच्चे से गोवा में मिला था. लंबे बाल, आंखों में बड़े सपने और स्वैग जो फिल्मों में छा जाना चाहता था.

संक्षिप्त समाचार

एलआईसी को एक लाख करोड़ रुपए की प्रीमियम आय

मुंबई। भारतीय जीवन बीम निगम एलआईसी को उसके पेंशन और समूह योजना खंड में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में रिकार्ड एक लाख करोड़ रुपए की प्रीमियम आय प्राप्त हुई है। एलआईसी ने मंगलवार को कहा कि यह पहला मौका है जब जीवन बीमा निगम के किसी एक खंड में इतनी बड़ी राशि प्रीमियम आय के रूप में प्राप्त हुई है। यह लगातार दूसरा साल है, जब इस खंड में अच्छी प्रीमियम आय प्राप्त हुई है। कंपनी के बयान के अनुसार समूह योजनाओं और सेवानिवृत्त कारोबार का प्रबंधन करने वाले इस खंड में प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति सात लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इन योजनाओं के जरिये एलआईसी कंपनियों को कर्मचारी सेवानिवृत्ति कोष प्रबंधन समाधान उपलब्ध कराती है। इस खंड में नये कारोबार प्रीमियम में उसकी बाजार हिस्सेदारी करीब 80 प्रतिशत है।

एस21 व गैलेक्सी बड्स प्रो की बिक्री शुरू

नई दिल्ली। सैमसंग ने देश में लुभावने ऑफर्स के साथ नवीनतम फ्लैगशिप गैलेक्सी एस21 सीरीज और गैलेक्सी बड्स प्रो की बिक्री शुरू कर दी है। गैलेक्सी एस21 सीरीज और गैलेक्सी बड्स प्रो बिक्री के लिए सैमसंग डॉटकॉम, सैमसंग के विशेष स्टोर सभी ऑनलाइन पोर्टल और खुदरा दुकानों में उपलब्ध होंगे। गैलेक्सी एस21 अल्ट्रा सैमसंग के आधुनिकतम और सबसे इंटेलीजेंट प्रो-ग्रेड कैमरा सिस्टम से लैस है और किसी भी गैलेक्सी स्मार्टफोन में मौजूद डिस्प्ले के मुकाबले सबसे ब्राइट और स्मार्ट डिस्प्ले के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का भरोसा देता है। गैलेक्सी एस21 प्लस और गैलेक्सी एस21 एक बेहतरीन आइकॉनिक डिजाइन के साथ ही एक एपिक प्रो ग्रेड कैमरा तथा किसी भी गैलेक्सी डिवाइस में इस्तेमाल हुए अब तक के आधुनिकतम प्रोसेसर के साथ आते हैं। इस सीरीज के तीनों स्मार्टफोन हाइपर फास्ट 5जी के लिहाज से तैयार हैं। सैमसंग अपग्रेड प्रोग्राम के तहत उपभोक्ताओं को पुराने स्मार्टफोन के बदले एक्सचेंज करने पर गैलेक्सी एस21 अल्ट्रा पर 7000 रुपए तक का अपग्रेड बोनस मिलेगा।

अडाणी एंटरप्राइजेज का शुद्ध लाभ घटा

नई दिल्ली। अडाणी एंटरप्राइजेज का चालू वित्त वर्ष की दिसंबर, 2020 में समाप्त तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 10.39 प्रतिशत घटकर 343.17 करोड़ रुपए रह गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 382.98 करोड़ रुपए का एकीकृत मुनाफा कमाया था। गौतम अडाणी की अगुवाई वाली कंपनी ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि तिमाही के दौरान उसकी एकीकृत कुल आय बढ़कर 11787.82 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 11075.32 करोड़ रुपए थी। तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 11303.97 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 10635.16 करोड़ रुपए था। अडाणी समूह की प्रमुख कंपनी ने बयान में कहा कि सौर विनिर्माण कारोबार की बिक्री बढ़ने की वजह से तिमाही के दौरान उसकी एकीकृत कुल आय छह प्रतिशत बढ़कर 11788 करोड़ रुपए पर पहुंच गई।

बजाज कंज्यूमर का मुनाफा बढ़ा

नई दिली। एफएमसीजी कंपनी बजाज कंज्यूमर केयर ने बताया कि दिसंबर 2020 को समाप्त तीसरी तिमाही के दौरान उसका संचयी लाभ 17.54 प्रतिशत बढ़कर 57.29 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने बताया कि इससे पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उसे 48.74 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। बजाज कंज्यूमर केयर ने शेयर बाजार को बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी कुल आय 16.25 प्रतिशत बढ़कर 257.61 करोड़ रुपए हो गई, जो इससे पिछले साल की समान अवधि में 221.60 करोड़ रुपए थी। कंपनी के बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के लिए छह रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की सिफारिश की है।

गेल को दो कंपनियों में बांटने का प्लान टला

नई दिल्ली। सरकार फिलहाल सरकारी क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड को दो कंपनियों में विभाजित नहीं करेगी। दरअसल, पहले सरकार की योजना गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग व्यवसाय के लिए गेल को दो कंपनियों में बदलने की थी और राज्य द्वारा संचालित कंपनी ने इसके लिए अर्नस्ट एंड यंग को एक सलाहकार के रूप में सौंपा था। इस कदम को देश के गैस बाजार में और अधिक पारदर्शिता लाने के कदम के रूप में देखा गया। हालांकि फिलहाल सरकार ने इस योजना हो होल्ड कर दिया है।

एसबीआई का एकल शुद्ध लाभ घटा

सात प्रतिशत घटकर 5196.22 करोड़ रुपए रहा मुनाफा

नई दिल्ली । देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने गुरुवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका एकल शुद्ध लाभ सात प्रतिशत घटकर 5196.22 करोड़ रुपए रहा। भारतीय स्टेट बैंक को पिछले वित्त वर्ष में अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में 5583.36 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि इस दौरान उसकी कुल आय घटकर 75980.65 करोड़ रुपए रही जो इससे पिछले वर्ष की समान अवधि में 76797.91 करोड़ रुपए थी।

बैंक ने बताया की तीसरी तिमाही में एकीकृत आधार पर उसका शुद्ध लाभ 5.8 प्रतिशत घटकर 6402.16 करोड़ रुपए रहा, जो इससे एक साल पहले की समान अवधि में 6797.25 करोड़ रुपए था। हालांकि, इस दौरान बैंक की परिसंपत्ति दिए गए ऋण की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ और अवरुद्ध ऋण एनपीए 31 दिसंबर 2020 तक कुल अग्रिम के मुकाबले घटक 4.77 प्रतिशत पर आ गई। एक साल पहले की समान अवधि में एनपीए 6.94 प्रतिशत थी। मूल्य के संदर्भ में सकल एनपीए या अवरुद्ध ऋण 117244.23 करोड़ रुपए था। इसी तरह शुद्ध एनपीए घटकर 1.23 प्रतिशत या 29031.72 करोड़ रुपए रह गया। नतीजों पर बात करते हुए बैंक के प्रबंधन का कहना है कि मुनाफे के लिहाज से ये तिमाही अच्छी रही है। एसेट क्वालिटी संभालने में कामयाब रहे है। तीसरी तिमाही में ग्रोथ फ्रंट पर भी बेहतर प्रदर्शन रहा है। सालाना आधार पर तीसरी तिमाही में होमलोन ग्रोथ 10 फीसदी रही है जबकि क्रेडिट ग्रोथ 6.73 फीसदी रही है। वहीं तीसरी तिमाही में रिटेल लोन ग्रोथ 15.57 फीसदी पर आई है।

एनटीपीसी का शुद्ध मुनाफा 10 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली। बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के तीसरी तिमाही में अच्छा परफॉर्म किया और इसका नेट प्रॉफिट 10 फीसदी बढ़कर 3315 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जबकि पिछले साल की समान अवधि में कंपनी को 2995 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। इसके साथ ही एनटीपीसी ने अपने शेयरहोल्डर्स को प्रति शेयर तीन रुपए अंतरिम लाभांश देने का भी ऐलान किया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लाभांश के पेमेंट की तिथि 26 फरवरी 2021 घोषित किया है। दिसंबर तिमाही में एनटीपीसी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू बढ़कर 24509 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 23496 करोड़ रुपए था। कंपनी ने दिसंबर तिमाही के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि नवंबर में अनाउंस किए गए शेयर बायबैक प्रोग्राम में सभी बिड्स का सेटलमेंट 30 दिसंबर, 2020 से पहले हो गया था। इसका वजह से कंपनी का पेडअप इक्विटी कैपिटल 198 करोड़ रुपए कम हो गया है। शेयर बायबैक प्रोग्राम के तहत कंपनी ने शेयरहोल्डर्स से 115 रुपए के भाव से 2275 करोड़ रुपए में 197891146 शेयर खरीदे हैं। यह कंपनी के 2 फीसदी टोटल पेडअप इक्विटी शेयर के बराबर है।

बाजार में तेजी जारी

सेंसेक्स 50,614 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर

मुंबई । वैश्विक स्तर पर मिले सकारात्मक संकेतों के साथ ही घरेलू स्तर पर आम बजट से उत्साहित निवेशकों की लिवाली के आज लगातार चौथे दिन जारी रहने के बल पर बीएसई का सेंसेक्स 50,614 अंक के रिकॉर्ड स्तर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का निफ्टी 105 अंक चढ़कर 14,895 अंक के पार बंद हुआ।

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 358.54 अंक बढ़कर 50,614.29 अंक पर और एनएसई का निफ्टी 105.70 अंक चढ़कर 14,895.65 अंक पर पहुंच गया। दिग्गज कंपनियों के साथ ही छोटी और मझोली कंपनियों में भी लिवाली का जोर बना रहा जिससे बीएसई का मिडकैप 1.45 प्रतिशत बढ़कर 19,594.94 अंक पर और स्मॉलकैप 1.21 प्रतिशत उछलकर 19,148.74 अंक पर बंद हुआ।बीएसई में आज कुल 3128 कंपनियों में कारोबार हुआ इनमें 1,857 कंपनियों के शेयर हरे निशान में और 1,123 के लाल निशान में बंद हुये जबकि शेष 148 कंपनियों के शेयर दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद अंततः अपरिवर्तित रहे।

किशोर बियानी को बड़ा झटका

सेबी ने एक साल के लिए किया बैन

मुंबई । अमेरिका की दिग्गज कंपनी ऐमजॉन के साथ विवाद में फंसे फ्यूचर ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव किशोर बियानी को बड़ा झटका लगा है। मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने किशोर बियानी और उनके भाई अनिल पर एक साल तक सिक्योरिटीज मार्केट में दाखिल होने पर रोक लगा दी है। सेबी ने फ्यूचर ग्रुप की रीटेल कंपनी फ्यूचर रीटेल के शेयरों में इनसाइर ट्रेडिंग भेदिया कारोबार जांच के बाद यह प्रतिबंध लगाया है।

सेबी ने कहा कि दोनों भाइयों फ्यूचर रीटेल के कुछ बिजनस के डिमर्जर से पहले अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इनफॉरमेशन के आधार पर एक ग्रुप कंपनी के जरिए फ्यूचर रीटेल के शेयरों की खरीद फरोख्त की। इससे कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी आई। इस बारे में फ्यूचर के प्रवक्ता और बियानी बंधुओं ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि बियानी बंधुओं ने फ्यूचर कॉरपोरेट रिसॉर्सेज के नाम पर एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला। उन्होंने फ्यूचर रीटेल की कंपनियों के डिमर्जर का फैसला सार्वजनिक होने से पहले इस अकाउंट के जरिए फ्यूचर रीटेल के शेयरों की खरीद-फरोख्त की। सेबी ने साथ ही दोनों भाइयों पर दो साल तक फ्यूचर रीटेल के शेयरों की ट्रेडिंग पर भी रोक लगा दी। ऐसे में किशोर बियानी फ्यूचर रिटेल के शेयरों की खरीद और बिक्री नहीं कर पाएंगे।

एक करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा

सेबी ने फ्यूचर कॉरपोरेट रिसॉर्सेज और बियानी बंधुओं पर प्रत्येक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें जुर्माने की राशि 45 दिन के भीतर जमा करनी होगी। किशोर बियानी ने फ्यूचर ग्रुप का रीटेल और होलसेल कारोबार पिछले साल मुकेश अंबानी की रिलायंस रीटेल को बेचने के लिए डील की थी। लेकिन अमेजॉन ने इसे कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर रीटेल लिमिटेड को रिलायंस रीटेल के साथ 24713 करोड़ रुपए के सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने को कहा। फ्यूचर ग्रुप का कहना है कि अगर यह डील नहीं हुई तो उसका रीटेल कारोबार बंद हो जाएगा।

बुलंद हौसले के साथ उतरेंगी भारत व इंग्लैंड की टीमें

विश्व चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने मुकाबला चेन्नई में, दोनों टीमों ने जीती है पिछली सीरीज

चेन्नई (एजेंसी)। भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार से एम चिदंबरम स्टेडियम में शुरु हो रही चार टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों टीमें आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से उतरेंगी। भारत और इंग्लैंड अपनी पिछली सीरीज जीतकर इस मुकाबले में उतर रही हैं। चेन्नई में पहले दोनों टेस्ट खेले जाएंगे। यह सीरीज विश्व चैंपियनशिप के लिहाज से खासी महत्वपूर्ण है और दोनों ही टीमों के लिए फाइनल में जगह बनाने का आखिरी मौका है। भारत ने अपनी पिछली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर 2-1 से हराया था जबकि इंग्लैंड की टीम श्रीलंका को 2-0 से क्लीन स्वीप कर भारत पहुंची है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत इस समय पहले स्थान पर है जबकि इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका का अपना आगामी दौरा स्थगित कर दिया है जिससे दूसरे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड ने फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल की दूसरे स्थान की टीम के लिए मुकाबला अब तीन टीमों भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिमट गया है। भारत और इंग्लैंड की सीरीज से ही फाइनल की दूसरी टीम का फैसला होगा जो इस साल जून में इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाना है। भारत-इंग्लैंड सीरीज का परिणाम ही तय करेगा कि इन तीन टीमों में से कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी। भारत नवंबर 2019 में कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में बंगलादेश के खिलाफ डे नाइट टेस्ट खेलने तथा कोरोना महामारी के बाद घरेलू जमीन पर अपना पहला टेस्ट खेल रहा है। कुछ खिलाड़ियों को छोड़कर भारत के सभी प्रमुख खिलाड़ी फिट हो चुके हैं और विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया को इंग्लैंड को चुनौती देने के लिए एक मजबूत एकादश चुननी है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जब चौथा और आखिरी टेस्ट जीता तो उसके कई प्रमुख खिलाड़ी चोटिल होकर उस मैच से बाहर थे और भारत ने कई नए खिलाड़ियों की बदौलत ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी।

इंशाम शर्मा व बुमराह फिट

भारत के दोनों शीर्ष तेज गेंदबाज इशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट हैं और चेन्नई में वह इंग्लैंड के सामने कड़ी चुनौती पेश करेंगे। इशांत ऑस्ट्रेलिया दौरे में नहीं खेले थे जबकि बुमराह चौथे टेस्ट से बाहर रहे थे। यदि तीसरे तेज गेंदबाज को खेलाने की नौबत आती है तो मोहम्मद सिराज की दावेदारी रहेगी और कुलदीप यादव को बाहर बैठन पड़ सकता है। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का खेलना तय है और यदि भारत तीन स्पिनरों के साथ उतरना चाहता है तो चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। कुलदीप ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट भी नहीं खेल पाए थे। तीसरे स्पिनर के लिए स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के मुकाबला रहेगा। सुंदर ऑफ स्पिन डालते हैं जबकि पटेल लेफ्ट ऑर्म स्पिनर हैं।

क्राउली चोट के कारण भारत के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैच से बाहर

इंग्लैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जैक क्राउली कलाई में चोट के कारण भारत के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार से चार टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई में खेला जाना है और मैच से ठीक एक दिन पहले ही क्राउली के चोटिल होकर पहले दो टेस्टों के लिए बाहर होने से इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने बयान जारी कर बताया कि क्राउली का स्कैन किया गया है। क्राउली के चोटिल होने के कारण इंग्लैंड को एक बार फिर से टीम संयोजन के बारे में विचार करना होगा। हालांकि निजी कारणों के चलते कुछ समय के लिए टीम से बाहर गए रोरी बर्न्स की टीम में वापसी हुई है। इस बीच कंधे की चोट से जूझ रहे ओली पोप भी फिट होकर खेलने के लिए उपलब्ध हो गए हैं। इसके अलावा कोरोना से जंग जीत चुके मोईन अली भी भारत के खिलाफ खेलने के लिए फिट हैं।

इंग्लैंड से ज्यादा भारत पर दबाव होगा: रूट

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रुट का कहना है कि शुक्रवार से भारत और इंग्लैंड के बीच शुरु हो रही चार मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड से ज्यादा भारत पर दबाव होगा। रूट ने कहा, इस बेहतरीन सीरीज का हिस्सा होना सुखद है। भारतीय टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराया था और हमारे पास टीम इंडिया को उसके घर में मात देने का मौका होगा। इंग्लैंड से ज्यादा दबाव टीम इंडिया पर होगा क्योंकि उनपर घरेलू जमीन में खुद के रिकॉर्ड को बरकरार रखने की चुनौती होगी। उन्होंने कहा, हमारी टीम में आत्मविश्वास है और हमने हाल ही में अच्छा क्रिकेट खेला है। टीम लगातार अपने खेल में सुधार कर रही है और अपनी रणनीति पर अमल कर रही है। मैं इस सीरीज के लिए काफी उत्साहित हूं। भारतीय कप्तान विराट कोहली और उनके प्रशंसकों के लिए विराट का मैदान पर वापसी करना सुखद होगा। हम हमेशा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ खेलना चाहते हैं और आप हमेशा सर्वश्रेष्ठ टीम को हराना चाहेंगे। हमारे लिए यह एक अच्छा अवसर है। यह काफी अच्छा मुकाबला होगा और मैं इसके लिए काफी उत्साहित हूं।

स्टोक्स व बटलर कर सकते हैं परेशान

इंग्लैंड को तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर से मजबूती मिलेगी जो श्रीलंका में नहीं खेले थे। आर्चर का साथ निभाने के लिए स्टुअर्ट ब्रॉड रहेंगे। टीम के पास बेन स्टोक्स और जोस बटलर के रुप में दो बेहद अनुभवी और स्टार खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। भारत की तरह इंग्लैंड की नजरें भी विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने पर टिकी हुई हैं। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सीरीज की दिशा तय करेगा और यह भी संकेत देगा कि कौन सी टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए तैयार है।

पंत खेलेंगे, कुलदीप को भी मिल सकता है मौका: विराट

चेन्नई। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार से यहां एमए चिदंबरम स्टेडियम में होने वाले पहले टेस्ट की पूर्व संध्या पर आज स्पष्ट कर दिया कि विकेटकीपर रिषभ पंत विकेट के पीछे जिम्मेदारी संभालेंगे और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को भी इस मुकाबले में मौका मिल सकता है। विराट ने पहले टेस्ट की पूर्व संध्या पर वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में टीम संतुलन को लेकर अपनी रणनीति को स्पष्ट किया। कप्तान ने कहा, रिषभ विकेट के पीछे खड़े होने जा रहे हैं। उनका हाल का प्रदर्शन शानदार रहा है। वह सफेद गेंद के फॉर्मेट का

हिस्सा नहीं थे लेकिन उन्होंने विकेटकीपिंग में अपनी मेहनत जारी रखी थी। हमने उनका बराबर समर्थन किया है और इसके अच्छे परिणाम को आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे विपक्षी टीमें भविष्य में डरेंगी। पंत ने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में ड्रॉ हुए टेस्ट में मैच बचाने वाली पारी खेली थी और ब्रिस्बेन के चौथे टेस्ट में मैच विजयी पारी खेली थी। इस प्रदर्शन का पंत को अब घरेलू जमीन पर भी फायदा मिलता दिखाई दे रहा है जहां टीम प्रबंधन और कप्तान ने उन्हें अनुभवी विकेटकीपर रिद्धिमान साहा पर प्राथमिकता दी है। विराट ने भारत के बल्लेबाजी क्रम को लेकर भी टीम की स्थिति स्पष्ट कर दी है। कप्तान ने साफ किया है कि सलामी बल्लेबाजी के लिए अनुभवी रोहित शर्मा और युवा शुभमन गिल उतरेंगे।